लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 25 जून, 2026
वर्ष : 11 । अंक: 299
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

सपनों की उड़ान वही भरते हैं, जिनके पंख हौसलों से बने होते हैं।

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi | NIGHT 29° Low

संक्षेप

अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

बेंगलुरु। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक कोर्ट ने अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है और अपने चुनावी हलफनामे में उन विवरणों को छिपाया था। बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ 3 बार एनबीडब्ल्यू जारी किया है, क्योंकि उन्हें समन नहीं भेजा जा सका था। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने 17 मार्च 2026 को निर्देश दिया था, शिकायतकर्ता के वकील उपस्थित हैं। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के माध्यम से आरोपी को पुनः समन जारी करें। इसके बाद कोई जवाब न आने पर 17 अप्रैल को कोर्ट को पता चला कि प्रकाश राज ने वो घर खाली कर दिया है, जहां समन भेजने का प्रयास हो रहा था। इसके बाद 12 जून को दोबारा वारंट जारी हुआ। मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। बेंगलुरु के निवासी के दिलीप कुमार ने एक निजी शिकायत दायर कर बताया कि प्रकाश राज ने 2019 में बेंगलुरु सेंट्रल से लोकसभा चुनाव लड़ते समय 22 मार्च को चुनावी हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया कि उनका नाम बेंगलुरु के शांतिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका नाम एक ही समय में 3 अन्य मतदाता सूचियों में था। इसमें चेन्नई स्थित वेलाचेरी विधानसभा और तेलंगाना का सेरिलिंगमपल्ली विधानसभा शामिल है।

दिल्ली में उद्योग भवन के पास लगी भीषण आग, मजदूरों के 200 अस्थायी घर जलकर खाक

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में उद्योग भवन के पास मजदूरों की एक बस्ती में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इसमें करीब 200 अस्थायी घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना तड़के 3 बजे की है। आग लगने की सूचना पर अग्निशमन दल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया है। यह पूरा इलाका सेना भवन के पास का बताया जाता है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना भवन के पास निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को रहने के लिए जगह दी गई थी और अस्थीय टिन शेड बनाया गया था। यहां कमरों में खाना पकाने के लिए छोटे रसोई गैस सिलेंडर भी थे और बिजली का कनेक्शन भी दिया गया था। बताया जा रहा है कि बिजली की स्पार्किंग की वजह से शेड में आग लगी होगी, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जांच जारी है। अग्निशमन दल के अधिकारियों के मुताबिक, जिस समय आग लगी, अधिकतर मजदूर अपने-अपने कमरों में सो रहे थे, जबकि कई लोग बाहर थे। आग लगने के बाद सभी सतर्क हो गए और बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की होई जनहानि नहीं हुई। यहां रहने वाले मजदूर बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं। आग लगने से मजदूरों का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि मजदूर सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य से जुड़े हैं।

'बागी सांसदों का नहीं आया कोई पत्र', लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद बोले उद्धव गुट के नेता

नई दिल्ली, एजेंसी। शिवसेना UBT के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और बागी गुट के संभावित पत्र को लेकर बात की। इस मामले में सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि पिछले हफ्ते हम आए थे और स्पीकर साहब को हमने निवेदन किया था। उस निवेदन में हमने यह कहा था अगर कोई सांसद व्यक्तिगत रूप से कहीं जाना चाहता है तो संविधान की रक्षा आपको करनी है। हमने उनसे यह कहा था कि आप बिना मेरी सुनवाई के कोई फैसला न लें। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज (बुधवार) शाम 5 बजे का उन्होंने हमें समय दिया था और उनसे मुलाकात हुई।

अरविंद सावंत ने बताया, 'हमने

स्पीकर साहब से कहा कि अगर कोई आपके पास बागी गुट का पत्र आया है तो हमें बताइए, पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है और हमें कागज नहीं मिला। हमने यह कहा कि जो संविधान का प्रावधान है, उस प्रावधान की रक्षा करने के हिसाब से किसी को भी मान्यता नहीं मिल सकती। अलग-अलग बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती'।

अनिल देसाई ने क्या कहा?

शिवसेना UBT के सांसद अरविंद सावंत के अलावा अनिल देसाई ने भी स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि 'स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि फैसला नियम के तहत ही होगा, उसको छोड़कर कोई इर्द-गिर्द बात नहीं होगी। उन्होंने यह कहा कि अगर कोई आवेदन बागी गुट की तरफ से आएगा, तो हम अपने ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे और जो भी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के हिसाब से हम फैसला करेंगे'।

सांसद अनिल देसाई ने कहा, 'हमने उनको जानकारी दी कि संविधान की 10वीं अनुसूची जो है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी का दो तिहाई बहुमत भी क्यों ना हो, वह किसी भी और दल में नहीं जा सकता। वह किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है और ना ही मर्ज हो सकता है। ओरिजिनल पार्टी जब कभी मर्जर करती है, उसी मर्जर को लेजिस्लेटर पार्टी के दो तिहाई बहुमत के साथ ही जा सकता है'।

एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं 6 सांसद

दरअसल, शिवसेना (UBT) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं, जबकि अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजभाऊ वाजे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के साथ बने हुए हैं। शिंदे खेमे में शामिल होने वाले सांसदों में नागेश अष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

2023 में शिंदे गुट को मिली थी मान्यता

चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। शिंदे ने ही साल 2022 में अविभाजित शिवसेना में विभाजन का नेतृत्व किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी।

राम मंदिर ट्रस्ट पर सिंधी समुदाय का गंभीर आरोप, 200 Kg चांदी ली, कोई रसीद नहीं दी

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए दान में कथित गड़बड़ियों को लेकर विवाद और बढ़ गया है। एक जाने-माने बिज़नेसमैन का दावा है कि मंदिर के लिए दान की गई 200 चांदी की ईंटों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। 'कासल्स ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़' के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजू वी. मनवानी ने बताया कि सिंधी समुदाय की ओर से, 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को एक-एक किलोग्राम वज़न वाली चांदी की 200 ईंटें सौंपी गई थीं। मंवाणी के अनुसार, दान के समय कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अधिकारियों ने दानदाताओं को बताया था कि चांदी का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाएगा, इस पर फ़ैसला बाद में लिया जाएगा।

मनवानी ने कहा कि मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी की हालिया खबरें मीडिया में आने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि चांदी का इस्तेमाल कहां होगा, लेकिन हाल की घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या चांदी का इस्तेमाल मंदिर के लिए किया गया था और अगर हां, तो कैसे।' उन्होंने आगे कहा कि अगर मंदिर के लिए दिया गया दान कहीं और इस्तेमाल किया गया, तो इससे भविष्य में दान देने वालों का भरोसा कम हो सकता है। दान के समय, चांदी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये थी। मनवानी के अनुसार, इसकी मौजूदा कीमत काफी बढ़ गई है और अब इसका अनुमान 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपये है।

मनवानी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दान देने वालों को धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों के लिए दिए गए दान के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार है।

खड़गे परिवार के ट्रस्ट ने हड़पी 100 करोड़ की जमीन? भाजपा ने लगाए बड़े आरोप, कर्नाटक में घमासान

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में ज़मीन के एक कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। यह मामला उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रस्ट को ज़मीन आवंटित करने से जुड़ा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि 2024 में, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट को लगभग पांच एकड़ इंडस्ट्रियल ज़मीन आवंटित की थी। भंडारी ने इस आवंटन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ट्रस्ट को इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव नहीं था और इसके बावजूद लगभग 100 करोड़ रुपये की

अनुमानित कीमत वाली ज़मीन उसे दे दी गई। भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटक में जमीन की लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, बेटे प्रियांक खड़गे, दामाद और उनकी पत्नी शामिल हैं। ये ट्रस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार का है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने इस ट्रस्ट के माध्यम से अलग-अलग जमीनों पर कब्जा किया और अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए गरीबों की जमीन हड़प ली। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 2024 में पांच एकड़ भूमि दी थी। उस समय कहा गया था कि यह ट्रस्ट एयरोस्पेस और डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करेगा। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है। लेकिन इस ट्रस्ट ने एयरोस्पेस और डिफेंस में अब तक कोई काम नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सदस्य हैं, 100 करोड़ की इंडस्ट्रियल जमीन क्यों दी? भंडारी ने कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके 5 एकड़ इंडस्ट्रियल जमीन पर कब्जा किया? उन्होंने कहा कि खड़गे जी, आप एक राजनेता हैं, आपके ट्रस्ट ने ऐसा कौन सा काम किया, जो एयरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च जमीन आपके प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई?

पीके का भोजपुर एनकाउंटर पर बड़ा बयान, बोले– पुलिस ने की हत्या, न्यायिक जांच हो!

नई दिल्ली, एजेंसी। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को भोजपुर ज़िले में 17 जून को हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 28 वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से मुलाक़ात की और मामले की न्यायिक जाँच की माँग की। पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस हत्या को अंजाम देने वालों और इसके लिए आदेश देने वालों, दोनों की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। हमारी माँग है कि जाँच में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल हो। भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर के मामले में 'भरत तिवारी संघर्ष समिति' ने बुधवार को एक महापंचायत की और चेतावनी दी कि अगर उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो वे बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन

करेंगे। यहाँ ANI से बात करते हुए, 'भारत तिवारी संघर्ष समिति' के एक सदस्य ने कहा कि प्रस्तावित सभा में लगभग एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और आंदोलन के और तेज़ होने की संभावना है। सदस्य ने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोग शामिल होंगे... अगर महापंचायत शुरू होने तक गिरफ्तारियां नहीं हुईं, तो हम बिहार में विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज़ हो सकता है, जिसमें राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और सड़कें जाम करना शामिल हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने भी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महापंचायत में लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक और बड़े पैमाने पर होगी। उन्होंने बताया कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से शामिल हो रहा है, किसी को खास तौर पर नहीं बुलाया गया है। इसलिए लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आरोपी को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए... हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जाए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले... यहां सभी का स्वागत है। वहीं, मृतक के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद वे इस आंदोलन को देश की राजधानी ले जाने की योजना बना रहे हैं।

प्रियांक खड़गे का तेजस्वी सूर्या पर पलटवार, बोले : पहले 'अच्छे दिन' का 'श्वेत पत्र' दिखाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर तीखा हमला किया। सूर्या ने बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर 'श्वेत पत्र' जारी करने की मांग की थी। इसके जवाब में खड़गे ने सुझाव दिया कि सूर्या को केंद्र सरकार से 'अच्छे दिन', सरकार के वादों और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत जैसे मुद्दों पर श्वेत पत्र मांगना चाहिए। इस घटनाक्रम से राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच विकास के दावों और आर्थिक कामकाज को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान का पता चलता है, जो खासकर बेंगलुरु में देखने को मिलती है।

पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से हैं, जिसका

मतलब है कि केंद्र सरकार आर्थिक नीतियों और राज्य पर उनके असर के बारे में बेहतर जानकारी दे सकती है। उन्होंने राज्य के कामकाज का बचाव करते हुए कहा कि कर्नाटक की आर्थिक विकास दर अभी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हर कोई कर्नाटक की आर्थिक स्थिति जानता है। उन्हें हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वे मोदी सरकार से ही पूछ सकते हैं, है ना? निर्मला सीतारमण कर्नाटक से वित्त मंत्री हैं। कर्नाटक राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें 'अच्छे दिन' का व्हाइट पेपर दिखाने... देने दीजिए। उन्हें दो करोड़ नौकरियों के वादे का व्हाइट पेपर देने दीजिए। उन्हें आ रहे निवेश पर व्हाइट पेपर देने दीजिए।

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर साधा निशाना, कर्नाटक में 19 एकड़ की सरकारी जमीन हड़पने के लगाए आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे व कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे पर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए कर्नाटक में जमीन की लूट और

भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि यह एक-दो मामले नहीं बल्कि कई मामले हैं जिनमें खरगे परिवार ने कथित तौर पर गरीबों की जमीन हड़पी है।

भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा 'कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 19 एकड़ जमीन खरगे के निजी ट्रस्ट को दे दी। इसका मतलब है कि 19 एकड़ सरकारी जमीन एक ट्रस्ट की निजी जमीन बन गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे समेत उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। तो क्या मल्लिकार्जुन खरगे ने सौदेबाजी के तहत अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके गुलबर्गा में ये 19 एकड़ जमीन हड़प ली?...'

गरीबों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप

हमारा आरोप है कि मल्लिकार्जुन खरगे और उनके बेटे एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटक में भूमि हड़पने और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस ट्रस्ट का नाम सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे, उनके बेटे प्रियांक खरगे, उनके दामाद और उनकी पत्नी शामिल हैं। उन्होंने एक दूसरे मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ दूसरा मामला नहीं है। मैं आपके सामने एक और मामला रखना चाहता हूं। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने बहुत अजीब काम किया। उन्होंने एक फर्जी विक्रेता खड़ा किया।

यह 100 करोड़ रुपये की एक प्रमुख औद्योगिक भूमि है

उन्होंने आगे कहा 'सवाल उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खरगे ने निजी ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटक में 100 करोड़ रुपये की पांच एकड़ औद्योगिक भूमि हड़पने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग किया? याद रखिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी-वड्रा परिवार। उनके बहनोई रॉबर्ट वड्रा सहित भी इसी तरह के भूमि हड़पने के आरोपों का सामना कर चुके हैं। यह मामले अभी भी चल रहे हैं। गांधी-वड्रा परिवार ने जिस तरीके से भूमि लूटी थी। उसी तरीके को मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धार्थ विनयरा ट्रस्ट के माध्यम से दोहराया है । यह 100 करोड़ रुपये की एक प्रमुख औद्योगिक भूमि।' आगे वे कहते हैं, 'मैं आपके सामने भूमि लूट का पहला मामला सिद्धार्थ विनयरा ट्रस्ट से संबंधित प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2024 में, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। मल्लिकार्जुन खरगे पार्टी अध्यक्ष थे अभी भी हैं, और प्रियांक खरगे मंत्री थे।

कांग्रेस का CM मोहन यादव पर बड़ा आरोप, परिवार ने खरीदी 111 एकड़ जमीन

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बुधवार को उज्जैन में कथित ज़मीन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 'उज्जैन मास्टर प्लान 2035' वाले इलाके में मोहन यादव के परिवार द्वारा ज़मीन खरीदने में हितों का टकराव है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने आरोप लगाया कि मोहन यादव के परिवार के सदस्यों ने उस इलाके में 168 एकड़ में से 111 एकड़ ज़मीन खरीदी, जहाँ 2028 में उज्जैन कुंभ का आयोजन होना है। इस मुद्दे को अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने जीतू पटवारी से कहा कि यह कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। यह और अयोध्या अंतरराष्ट्रीय मामले हैं। लोगों की आस्था इन शहरों से जुड़ी है। लोग तीर्थयात्रा पर जाने के लिए पाई-पाई जोड़ते हैं। पैसे की लूट या चोरी करना लोगों की आस्था पर चोट करने जैसा है। आप (मोहन यादव) मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसलिए फाइलें आपकी टेबल से होकर गुज़रती हैं।

24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, डंडे से पिटाई और पिटबुल का पहरा... फैक्ट्री में 2 साल से बंधक थे मजदूर, कैसे बचाया गया?

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बंधुआ मजदूरी और मजदूरों के शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तितावी थाना क्षेत्र के माड़ी गांव स्थित दोने बनाने की फैक्ट्री में पुलिस, लेबर विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 12 मजदूरों को मुक्त कराया है। आरोप है कि इन मजदूरों को पिछले करीब दो साल से बंधक बनाकर रखा गया था और उनके साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार किया जाता था।

पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री में काम कराने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों और नेपाल से गरीब मजदूरों को पैसे और नौकरी का लालच देकर लाया गया था। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री पहुंचने के बाद उनके मोबाइल फोन और आधार कार्ड छीन लिए गए। इसके बाद उन्हें बाहर जाने या किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं दी जाती थी।

24 घंटे में सिर्फ एक बार चोकर की रोटी

मजदूरों ने बताया कि उनसे जबरन काम कराया जाता था और मजदूरी देने की बात कहकर बुलाने वाले लोगों ने बाद में कोई भुगतान नहीं किया। आरोप है कि उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बार सूखी चोकर की रोटी दी जाती थी। विरोध करने या काम में देरी होने पर लाठी-डंडों से पीटा जाता था।

मामले का खुलासा तब हुआ जब फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर किसी तरह वहां से भाग निकला और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। सूचना के बाद लेबर विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने 12 मजदूरों को मुक्त कराया। मुक्त कराए गए मजदूरों ने पुलिस को बताया कि फैक्ट्री में उनकी निगरानी के लिए दो पिटबुल कुत्ते भी रखे गए थे। आरोप है कि मजदूरों को डराने और भागने से रोकने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने मौके से मजदूरों की पिटाई में इस्तेमाल किए जाने वाले डंडे और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि मुक्त कराए गए मजदूरों के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं और सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मजदूरों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने इस मामले में शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों मजदूरों को अलग-अलग जगहों से फैक्ट्री तक लाने का काम करते थे। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

मजदूर ने बताई कहानी

मुक्त कराए गए मजदूर जगदीश ने बताया कि उन्हें अंबाला से 8 हजार रुपये महीने और खाने-पीने का लालच देकर लाया गया था, लेकिन यहां आने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। उसने आरोप लगाया कि न तो पैसे दिए गए और न ही ठीक से खाना दिया गया। उसने बताया कि मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिए गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर मजदूरों की मौत से जुड़े आरोपों की पुष्टि होती है तो मुकदमे में संबंधित धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी।

सपा ने रानी दुर्गावती को बलिदान दिवस मनाया

जौनपुर। समाजवादी पार्टी जौनपुर द्वारा गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके साहस, शौर्य और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया। रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपने स्वाभिमान और राज्य की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त की थी, जिसके सम्मान में यह दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की महान वीरांगनाओं में से एक थीं, जिन्होंने अन्याय और आक्रमण के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। गोष्ठी को पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, अशोक यादव नायक आदि ने संबोधित किया।

बाराबंकी में जलाभिषेक से पहले नहाने गए दो सगे भाई गोमती नदी में डूबे, गोताखोरों ने निकाले शव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बाराबंकी। अवसानेश्वर मंदिर में बुधवार को दर्शन व जलाभिषेक करने गए दो सगे भाइयों की गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। गोताखोरों ने दोनों के शव नदी से बाहर निकाले।

लोनीकटरा के बुढनापुर के अशोक पाण्डेय के 18 वर्षीय पुत्र गजेंद्र पाण्डेय उर्फ हनी और 14 वर्षीय देवेंद्र पाण्डेय उर्फ हैप्पी बुधवार को हैदरगढ़ में अवसानेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन करने गए थे। जलाभिषेक से पहले दोनों मंदिर किनारे स्थित गोमती नदी के स्नान घाट पर नहाने उतर गए।

बताते हैं कि नहाते समय एक भाई गहरे पानी में पहुंचकर डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भाई भी नदी में समा गया। दोनों भाइयों को डूबता देख घाट पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे गोताखोरों ने काफी प्रयास के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की खबर मिलते ही स्वजन बदहवास हो गए। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

मोहन यादव के भ्रष्टाचार पर हल्ला मचाकर क्या छिपा रहे हैं अखिलेश यादव, उठाए जमीनों पर सवाल : ओपी राजभर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मप्र जमीन खरीद विवाद पर मोहन यादव का नाम आने के बाद अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया था। अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। यूपी कैबिनेट में मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप? ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं? अब बताता हूं, आपकी पीड़ा क्या है? आप क्यों घबरा गए! कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए?

अखिलेश जी! एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे

आपने अपना रिश्ता छिपा लिया। अखिलेश जी भरत यादव आपके ₹कुबेर₹ चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष रहे हैं। उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा।

अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से आप डर गए? मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा- यह भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है। जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं।

इस मामले में अखिलेश जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है। और जमीन 'खाने' के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है। इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे में सैफई परिवार ने यही किया था। फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी गईं और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया।

निजी फायदे के लिए सैफई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किमी और ज्यादा बढ़ा दी गई। औने-पौने दाम में जमीनों को खरीदकर भारी भरकम मुआवजा वसूला गया।

सपाई लोडरों!

गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी न हो जाए, जिससे उनका निवेश डूब जाए। जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से सफेदपोश निवेशक शामिल हैं।

क्या बोले थे मोहन यादव पर अखिलेश

जमीन खरीद विवाद को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। इस पूरे विवाद को साजिश बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची है, उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या बीजेपी को पता नहीं था कि मोहन यादव रियल इस्टेट का काम करते थे।

बकौल अखिलेश यादव, ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि तीन मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, इन्हें मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है।

नशे के कथित कारोबार के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के बघराजपुर मोहल्ले में कथित रूप से चल रहे नशे के कारोबार के विरोध में स्थानीय महिलाएं एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने शिकायती पत्र सौंपकर इलाके में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

शिकायत लेकर पहुंचीं महिलाओं ने अपनी बारी का इंतजार किया और बाद में अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह के सामने अपनी बात रखी। महिलाओं का आरोप है कि मोहल्ले में लंबे समय से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों खासकर महिलाओं और बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने बताया कि सुबह से शाम तक कथित तौर पर नशे के खरीदारों और संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों पर पहले भी कार्रवाई और जेल भेजे जाने की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन रिहाई के बाद फिर से गतिविधियां शुरू होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे अपने मोहल्ले में सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण चाहती हैं और प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद कर रही हैं।

17 साल के भतीजे से बनाती थी शारीरिक संबंध, ब्लैकमेल कर फंसाया जाल में, अब गर्भवती होने का दावा कर रही रिश्ते की चाची

आर्यावर्त संवाददाता

इगलास (अलीगढ़)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता द्वारा अपने ही रिश्ते के एक 17 वर्षीय नाबालिग भतीजे को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन अवैध शारीरिक संबंध बनाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।

किशोर की मां की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित चाची के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

ढाई साल से ब्लैकमेल कर रही थी दो बच्चों की मां

पीड़ित किशोर की मां द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार पड़ोस में रहने वाली और रिश्ते में चाची लगने वाली तीन बच्चों की मां ने उसके बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। महिला पिछले करीब दो-ढाई वर्षों से किशोर के साथ लगातार अवैध संबंध बनाती आ रही थी। हद तो तब हो गई जब महिला उसे हमेशा के लिए अपना बनाने का दबाव डालने लगी।

वह किशोर को लगातार धमकी दे रही थी कि यदि उसने संबंध तोड़े या साथ रहने से मना किया, तो वह उसे दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देगी। इस लगातार मिल रही धमकी से भयभीत होकर जब परेशान किशोर ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

भतीजे से ढाई माह की गर्भवती होने का दावा

इंस्पेक्टर डीके सिसौदिया ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर होने के कारण ग्रामीणों के अनुरोध पर गांव में एक सामाजिक पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत में महिला के पति और अन्य परिजनों ने उसे सामाजिक लोक-लाज का हवाला देते हुए काफी समझाने का प्रयास किया। समझाने पर उसका पति उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार भी था, लेकिन महिला किसी भी कीमत पर अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हुई। उसने भरी पंचायत में खुलकर स्वीकार किया कि वह अपने नाबालिग भतीजे के साथ हुए संबंधों के चलते ढाई महीने की गर्भवती है और वह सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है।

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई जेल

महिला द्वारा पति के साथ रहने से साफ इनकार करने और नाबालिग के उत्पीड़न की बात पुख्ता होने के बाद पुलिस ने तत्काल कड़ा रुख अपनाया। इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

पत्रकारों ने लखनऊ अग्निकांड में दिवंगत छात्रों को नम आंखों से किया याद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड में असमय काल के गाल में समाए छात्रों की स्मृति में आज जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले जिले के पत्रकारों एवं समाजसेवियों द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल सचिव के निर्देशन एवं जिलाध्यक्ष की अगुवाई में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने कैंडल जलाकर दिवंगत छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। जिन छात्रों ने अपने भविष्य और सपनों को संवारने के लिए कोचिंग का रास्ता चुना था, उनका इस तरह असमय चले जाना बेहद पीड़ादायक और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। कार्यक्रम में जिले के समाजसेवी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पत्रकार राकेश शर्मा, नीरज तिवारी, शरद श्रीवास्तव, दीपक मिश्रा, रामानंद मिश्रा, राजदेव शुक्ला, रामराज पाण्डेय, अफ्तार अहमद, मो. अरबाब, विजय धर पाठक, कृतेश सेन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा के अंत में सभी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक अपील भी की।

श्रीराम मंदिर चोरी प्रकरण में कांग्रेस का प्रदर्शन

जौनपुर। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के आरोपों को लेकर बुधवार को जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई। वक्ताओं का कहना था कि श्रीराम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं, इसलिए मंदिर से जुड़े किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक विवाद की पारदर्शी जांच आवश्यक है ताकि लोगों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान हो सके । कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने कहा कि मंदिर से जुड़े मामलों में यदि किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप सामने आए हैं तो उनकी विधिसम्मत जांच होनी चाहिए।

कानपुर में 3200 करोड़ का महाघोटाला, ED की रडार पर आए 12 बड़े बैंक, 68 फर्जी खातों से हुआ था करोड़ों का अवैध लेनदेन

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर (Kanpur) में 68 खातों के जरिए 3200 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लेनदेन हुआ। अब इस मामले में 12 बैंक ईडी (ED) की जांच के दायरे में आ गए हैं। इन 12 बैंकों में ही आरोपितों ने 68 खाते खुलवाए थे। इन बैंकों में 68 खाते खुलवाने में कौन से दस्तावेज लगे और एक-एक दिन में किन आधार पर करोड़ों रुपये निकाले गए। इनकी जांच होगी। प्रकरण में ईडी ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वहीं, पुलिस आरोपितों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा भी जुटा रही है। पुलिस ने जाजमऊ के टेनरी व स्क्रैप कारोबारी महफूज आलम उर्फ पप्पू छूरी वाला के 3200 करोड़ से अधिक के अवैध साम्राज्य के मास्टरमाइंड महफूज के साले महताब आलम, उसके बेटे मासूम को सबसे पहले जेल

भेजा था। उसके बाद महफूज को भी गिरफ्तार किया। बाद में इस अवैध साम्राज्य के वजीर फिरोज खान, राजदार यशोदा नगर के राजीव नगर निवासी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है, जबकि गुरुवार को गिरोह के नूर आलम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। 3200 करोड़ 12 बैंकों के 68 खातों में हुए थे। इसमें एचडीएफसी बैंक में 14 खाते, आरबीएल बैंक में पांच, इंडसइंड बैंक में पांच, कोटक महिंद्रा बैंक में छह, यूनियन बैंक के चार, एक्सिस बैंक में तीन, बंधन बैंक के चार, आइसीआइसी बैंक के दो, सिटी यूनियन बैंक के सात, बैंक आफ बड़ौदा में दो, बैंक आफ इंडिया में एक खाता है।

बोगस फर्में बना रखी थी महफूज के गिरोह ने

महफूज के इस पूरे गिरोह ने 400 से अधिक टेनरी, स्क्रैब और स्लाटर हाउस के नाम पर बोगस फर्में बना रखी थीं। प्रकरण में मनी लांड्रिंग की आशंका पर ईडी ने बीते सप्ताह आरोपितों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज कर जांच और तेज कर दी।

ईडी ने कानपुर पुलिस से मांगे थे दस्तावेज

कानपुर पुलिस से इस मामले में सभी आरोपितों का ब्योरा व उससे जुड़े बरामद दस्तावेज और पुलिस की जांच के दस्तावेज मांगे थे। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया ईडी की दायरे में अब 12 बैंकें भी हैं। उसके बारे में ब्योरा मांगा गया है। इतते खाते किस आधार पर खुले और करोड़ों का लेनदेन एक दिन में हुए। इन सबकी जांच ईडी अब करेगी।

मास्टर माइंड का बेटा 25 हजार का इनामी फरार

मास्टर माइंड महफूज आलम का बेटा फैज अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस अधिकारी ने उसके खिलाफ 25 हजार का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।

ऐसे हुआ था इस गिरोह का पर्दाफाश

श्याम नगर ने 16 फरवरी को यशोदा नगर के वासिद व साथी अरशद को तमंचा लगा आठ लाख रुपये लूटने की सूचना मिली थी। पुलिस पहुंची तो दोनों ने बाद में लूट से इन्कार कर दिया था। बार-बार उनके बयान बदलने पर शक हुआ और जांच शुरू की तो पता चला कि दोनों युवक जाजमऊ के टेनरी व स्क्रैप कारोबारी जाजमऊ के जेके कालोनी निवासी महफूज आलम उर्फ पप्पू छूरी वाला के लिए काम करते थे। उस दिन वासिद और उसका साथी महफूज के बताने पर शिवांश टेनरी के नाम पर फूलबाग के आइडीबीआइ बैंक में खुले खाते से 3120 करोड़ निकाले थे, जिसमें से महफूज के बेटे फैज, साले महताब और रिश्तेदारों को 2195 करोड़ देकर शेष रकम 25 लाख लेकर महफूज को देने उसके घर जा रहे थे।

मुठभेड़ में पकड़े गए थे दो आरोपित

मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में दो और उनकी निशानदेही पर दो और लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि प्रकरण की जांच आगे बढ़ी तो महफूज का एक बड़ा गिरोह का पता चला। पुलिस और आयकर विभाग की जांच में महफूज, उसकी पत्नी शायदा, बेटे फैज, बेटी एनम, भाई मिशब, साले मेहताब, उसका बेटा मासूम समेत लोगों के की फर्म के नाम से 12 बैंकों में खुले 68 खातों में सवा दो साल में लगभग 3200 करोड़ का लेनदेन पाया गया।

वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जौनपुर। जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के कोचारी गांव के समीप तीन जिलों की सीमा पर स्थित एक वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्यटकों में चिंता बढ़ती जा रही है। जौनपुर, वाराणसी और भदोही समेत आसपास के जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहां मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े मुद्दों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।पर्यटकों के अनुसार वाटर पार्क घने बबूल के जंगलों और नदी के किनारे स्थित है। मुख्य मार्ग से पार्क तक पहुंचने वाला करीब पांच से छह किलोमीटर लंबा रास्ता काफी सुनसान रहता है। शाम ढलने के बाद इस मार्ग पर आवागमन और भी कम हो जाता है। लोगों का कहना है कि रास्ते में न तो कोई पुलिस चैकी है जिससे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। ऐसे में विशेषकर महिलाओं और परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों को असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ता है।

बिजली आपूर्ति में प्रदेश अव्वल, भीषण गर्मी में भी व्यवस्था सुचारु, ग्रामीण क्षेत्रों में रिकॉर्ड सप्लाई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी का असर साफ देखने को मिल रहा है। गर्मी के इस कठिन दौर में भी यूपी में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में हुए सुधार को सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। योगी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22.5 घंटे तक लगातार बिजली आपूर्ति की जा रही है।

मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24-24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं पीक डिमांड बिजली आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश ने अपने और देशभर के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 23 जून की रात 22.26 बजे यूपीपीसीएल ने रिकॉर्ड 32405 मेगावाट बिजली आपूर्ति की।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही 23 से 24 घंटे बिजली

यूपीपीसीएल की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। 19 जून को 23.55 घंटे, 20 जून को 23.48 घंटे, 21 जून को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। इसी तरह गाजियाबाद में 19 जून को 23.53 घंटे, 20 जून को 23.53 घंटे और 21 जून को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। लखनऊ में भी 19 जून को 23.58 घंटे, 20 जून को 22.54 घंटे और 21 जून को 23.12 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। बरेली में 19 जून को 23.55 घंटे, 20 जून को 20.43 घंटे और 21 जून को 22.10 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। शाहजहांपुर में 19 जून को 23.59 घंटे, 20 जून को 22.41 घंटे और 21 जून को 23.19 घंटे बिजली आपूर्ति की गई।

इस समय 20 से 24 घंटे तक हो रही बिजली सप्लाई

योगी सरकार के कार्यकाल में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए गए हैं। इसका परिणाम यह है कि आज प्रदेश के लाखों ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कहीं बेहतर बिजली सुविधा मिल रही है।ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शेड्यूल निर्धारित है, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए निर्धारित शेड्यूल से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे से लेकर 24 घंटे तक बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।

2017 से पहले सिर्फ 11 घंटे ही था बिजली आपूर्ति का शेड्यूल

गर्मी के मौसम में जहां पहले बिजली कटौती बड़ी समस्या बन जाती थी, वहीं अब लंबे समय तक निर्बाध बिजली आपूर्ति से लोगों को काफी राहत मिल रही है। इससे न केवल घरेलू जीवन आसान हुआ है बल्कि छोटे व्यवसायों, किसानों और छात्रों को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर वर्ष 2017 से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का शेड्यूल लगभग 11 घंटे का हुआ करता था। वास्तविक स्थिति इससे भी खराब थी, क्योंकि अधिकांश गांवों में सिर्फ 8 से 11 घंटे ही बिजली मिल पाती थी। कई क्षेत्रों में अघोषित कटौती आम बात थी। 2017 से पहले सिर्फ कुछ ही चिन्हित वीआईपी जनपदों में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती थी।

हर स्तर पर हो रही लगातार मॉनिटरिंग

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि कारपोरेशन और डिस्काम के अधिकारी व कर्मचारी सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सजकता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। हर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी के दिनों में बेहतर विद्युत आपूर्ति मिले, इसके लिए कारपोरेशन पूरी तरह से प्रयासरत है।

76वें वन महोत्सव पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का शुभारंभ, प्रदेशभर से चुने जाएंगे 76 हरित सारथी

लखनऊ। 76वें वन महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा "वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 – एक पेड़ माँ के नाम" अभियान का शुभारंभ डिजिटल जन-जागरूकता कार्यक्रम 'हरित सारथी अभियान' तथा जलवायु परिवर्तन विषयक चर्चा के साथ किया गया। इस पहल का उद्देश्य वृक्षारोपण को जनभागीदारी के माध्यम से एक सशक्त जन आंदोलन का स्वरूप देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से कुल 76 हरित सारथियों का चयन किया जाएगा। चयनित हरित सारथी अपने-अपने क्षेत्रों में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे तथा अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का कार्य करेंगे।

मड़ियांव पुलिस ने अपहृत नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया, दो युवक गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मड़ियांव पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले का सफल खुलासा करते हुए उसे सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।पुलिस के अनुसार 18 जून 2026 को एक व्यक्ति ने थाना मड़ियांव में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को लाल बाबू नामक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना मड़ियांव में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी।मामले की विवेचना के दौरान 23 जून को थाना मड़ियांव की पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिस किशोरी की तलाश की जा रही है, वह आईआईएम रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप के आगे यादवपुरवा जाने वाले रास्ते के पास दो युवकों के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों युवकों के साथ नाबालिग किशोरी को बरामद कर लिया।पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपनी पहचान लाल बाबू (20) पुत्र स्वर्गीय प्रसादी तथा अरुण (19) पुत्र राकेश, दोनों निवासी ग्राम बेहटा, थाना गुडम्बा, लखनऊ के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान अरुण का नाम भी मामले में प्रकाश में आया था।पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की गई।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है तथा आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानों और जनपदों से जुटाई जा रही है।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राजदीप चौधरी, उपनिरीक्षक ज्ञानेन्द्र गौड़, कांस्टेबल अभय कुमार तथा महिला कांस्टेबल मंशा पाण्डेय शामिल रहीं।

बैंकॉक से मंगाई जा रही थी हाईटेक ड्रग्स, लखनऊ में 20 लाख की ओजी के साथ तस्कर दबोचा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस से पहले लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स सेल ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित ओजी (ओशन ग्रोन टीएचसी/हाइड्रोपोनिक वीड) बरामद की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उस नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है, जिसके तार बैंकॉक (थाईलैंड) तक जुड़े होने की बात सामने आई है।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा "नशा मुक्त अभियान" के तहत 17 जून से 26 जून तक विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की ऑर्गनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन पर एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर में एक व्यक्ति

प्रतिबंधित मादक पदार्थ ओजी की बिक्री और आपूर्ति कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के बाद नारकोटिक्स सेल ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए 23 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सैय्यद जॉन पुत्र मोहम्मद शब्बू निवासी सज्जादिया कॉलोनी, आलमनगर, थाना तालकटोरा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तीन पैकेटों में रखी 300 ग्राम प्रतिबंधित ओजी बरामद की गई। इसके अलावा मादक पदार्थ की ढुलाई में इस्तेमाल की जा रही एक टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी भी जब्त की गई है।पुलिस के मुताबिक बरामद ओजी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है। बरामद मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी में पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ थाना तालकटोरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।पूछताछ और विवेचना के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोग गेमिंग एप के माध्यम से संपर्क में रहते थे और उसी के जरिए सौदों एवं आपूर्ति की जानकारी साझा करते थे। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि प्रतिबंधित ओजी को बैंकॉक से अवैध माध्यमों द्वारा भारत लाया जाता था और बाद में लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में सक्रिय छोटे तस्करों तथा स्थानीय सप्लायरों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था।पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार आरोपी इस नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, जो स्थानीय स्तर पर मादक पदार्थ की सप्लाई सुनिश्चित करता था। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए विस्तृत जांच कर रही है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, चिनहट पुलिस की कार्रवाई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। चिनहट पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे काशीराम कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार थाना चिनहट में 23 जून 2026 को एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उससे शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इंकार कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर थाना चिनहट में मुकदमा संख्या 340/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 351(3) और 74 में मामला दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक चिनहट ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल विशेष टीम गठित की। विवेचक उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना तंत्र को सक्रिय किया और मुखबिर की सूचना पर नामजद आरोपी महताब अली को काशीराम कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान महताब अली पुत्र हियात अली, निवासी बेतौली, जनपद अयोध्या तथा वर्तमान निवासी लौलाई, थाना चिनहट, लखनऊ के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई गई है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अलीगंज के पुरनिया सेक्टर-डी स्थित कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने बुधवार को हादसे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ केजीएमयू पहुंचकर घायल युवक का हालचाल जाना तथा चिकित्सकों से उसके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद महापौर ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हादसे में जान गंवाने वाले युवाओं के परिजनों से मुलाकात की और इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।महापौर ने केजीएमयू में भर्ती ऐशबाग निवासी जयंत कुमार का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की प्रगति की जानकारी लेते हुए घायल के शीघ्र

स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके बाद वह गुडम्बा के मायापुरी क्षेत्र पहुंचीं, जहां उन्होंने अग्निकांड में दिवंगत हुए सागर पंत के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।कमता चिनहट स्थित ज्ञान विहार कॉलोनी में महापौर ने ज्योति के परिजनों से भेंट की। उन्होंने कहा कि एक बेटी का इस प्रकार असमय परिवार से बिछड़ जाना अत्यंत दुखद और असहनीय है। उन्होंने परिवार को धैर्य रखने का संबल देते हुए कहा कि पूरा शहर इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है।मार्टिनपुरवा, गौतमपल्ली में महापौर ने नीलेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि एक होनहार युवा का इस तरह असमय निधन समाज और परिवार दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं आदर्श नगर, आलमबाग में सुखमणी सिंह के परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक व्यक्त किया और परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।उतरठिया के शांति नगर, बाधेखेड़ा क्षेत्र में महापौर ने 25 वर्षीय अनुक्षा राई के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इतनी कम आयु में एक बेटी का निधन अत्यंत मर्मांतक है और इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि अलीगंज अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। नगर निगम लखनऊ और पूरा शहर इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

संक्षेप

गाजीपुर में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर के पास लगी आग, नगर निगम की कूड़ा गाड़ी भी चपेट में आई

लखनऊ। गाजीपुर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर चौकी अंतर्गत कन्वेंशन सेंटर के पास मंगलवार देर रात बिजली के खंभे में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में ट्रांसफार्मर के समीप खड़ी नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया।पुलिस के अनुसार डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्वेंशन सेंटर के निकट स्थित बिजली के खंभे में आग लग गई है और पास में खड़ी नगर निगम की गाड़ी भी जलने लगी है। सूचना मिलते ही थाना गाजीपुर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और संभावित खतरे को देखते हुए बिजली विभाग से समन्वय स्थापित कर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि या बड़ा हादसा टाला जा सके।इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उसे पूरी तरह बुझा दिया। साथ ही नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर हटवाया गया तथा आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर आवश्यक राहत कार्य किए गए।घटनास्थल पर नगर निगम जोन-7 के वार्ड लाल बहादुर शास्त्री प्रथम के गार्ड सूर्य प्रकाश शुक्ला सहित अन्य स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।

मोहनलालगंज में युवक ने हाईटेंशन लाइन के खंभे से फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

लखनऊ। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मनोहरापुर गांव में बुधवार सुबह एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह करीब छह बजे सूचना प्राप्त हुई कि मनोहरापुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही सीसेंडी चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान अंकुश (20) पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद निवासी मनोहरापुर, थाना मोहनलालगंज के रूप में हुई। बताया गया कि युवक ने खेत में स्थित हाईटेंशन लाइन के खंभे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और परीक्षण की कार्रवाई की।पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मृत्यु के वास्तविक कारणों तथा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

किसान पथ पर खड़े कंटेनर से टकराई बाइक, 22 वर्षीय युवक की मौत

लखनऊ। बिजनौर थाना क्षेत्र में किसान पथ स्थित नटकुर अंडरपास के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब एक मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया।पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही थाना बिजनौर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या यूपी-32-जीयू-1467 पर सवार युवक किसान पथ पर खड़े कंटेनर संख्या एचआर-55-एडब्ल्यू-4082 से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल युवक की पहचान शिवम उर्फ बलदेव (22) पुत्र नंदन निवासी नटकुर चंद्रावल, थाना बिजनौर के रूप में हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने कंटेनर और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस से पहले लखनऊ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख रुपये की प्रतिबंधित ओजी बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस तथा "नशा मुक्त अभियान" के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 20 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित ओजी (ओशन ग्रोन टीएचसी/हाइड्रोपोनिक वीड) बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस के अनुसार 17 जून से 26 जून तक चलाए जा रहे विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान के दौरान क्राइम ब्रांच को हाल ही में शुरू की गई ऑर्गनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन पर एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में बताया गया था कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित मादक पदार्थ ओजी की बिक्री और आपूर्ति में सक्रिय है। सूचना का सत्यापन करने

के बाद क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स सेल ने 23 जून को कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सैय्यद जॉन पुत्र मोहम्मद शब्बू, निवासी संजय प्रिय कॉलोनी, आदिलनगर, लखनऊ के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तीन पारदर्शी पैकेटों में रखी कुल 300 ग्राम प्रतिबंधित ओजी बरामद की गई। इसके अलावा मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त एक टीवीएस एनटॉर्क स्कूटी भी जब्त की गई है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद ओजी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये है। बरामद मात्रा अधिसूचित वाणिज्यिक सीमा से अधिक पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना तालकटोरा में एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। पूछताछ में पता चला कि नेटवर्क से जुड़े लोग गेमिंग एप के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे। प्रतिबंधित मादक पदार्थ को कथित तौर पर बैंकॉक (थाईलैंड) से अवैध माध्यमों से भारत लाया जाता था और इसके बाद लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों पर छोटे तस्करों एवं स्थानीय सप्लायरों के जरिए इसकी आपूर्ति की जाती थी। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रही है।पुलिस के मुताबिक ओजी कैनाबिस वर्ग का एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित मादक पदार्थ है, जिसे नियंत्रित वातावरण में हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार किया जाता है। इसमें सामान्य गांजे की तुलना में टीएचसी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका नशीला प्रभाव और अवैध बाजार मूल्य भी अधिक होता है। युवाओं के बीच इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए तस्कर नेटवर्क इसकी आपूर्ति में सक्रिय रहते हैं।

बीएसएनएल की भारतनेट उद्यमी योजना से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से भारतनेट उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नवयुवक और युवतियां अपने गृह जनपद में रहकर कम पूंजी में व्यवसाय शुरू कर सकेंगे तथा आय का नया स्रोत विकसित कर सकेंगे।दूरसंचार जिला, व्यापार क्षेत्र, लखनऊ द्वारा संचालित इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) सेवाओं के विस्तार के लिए नए उपभोक्ताओं को जोड़ने का कार्य सौंपा जाएगा। बीएसएनएल की ओर से उद्यमियों को आकर्षक भुगतान के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।बीएसएनएल अधिकारियों के अनुसार यह योजना प्रधानमंत्री की डिजिटल भारत परिकल्पना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।योजना से जुड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9434053427 एवं 9455004700 पर संपर्क किया जा सकता है।

अपने घरों की ओर भी लौटें घरेलू पर्यटक

उदारीकरण के पहले तक गर्मी की छुट्टियों का मतलब, जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकी छुट्टियां होती थीं, स्कूल बंद हो जाते थे, अदालतों में जरूरी फौजदारी मामलों को छोड़ सुनवाई रूक जाती थी, और अदालतें बंद हो जाती थीं, तहसीलों में भी सूनापन छा जाता था, बैंकों में भी आधे से ज्यादा लोग गर्मी की छुट्टियां ले लेते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सूचना और संचार क्रांति के कारण पहले की तुलना में बिजली ज्यादा मिलने के चलते अब शहरों को कौन कहें, गांव तक पूरी रात गुलजार हो रहे हैं। इसका असर छुट्टियां मनाने के अंदाज और छुट्टियों के लिए जगह के चयन पर भी पड़ रहा है। अब छुट्टियों का मतलब साफ तौर पर बदल गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी, ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। गांवों में वे ही लोग रह रहे हैं, जिनके पास जायदाद ज्यादा है या जिनकी हैसियत नहीं है कि शहर जा सकें। उत्तर भारत के गांवों का दौरा करेंगे तो पाएंगे कि हर तीसरे घर में या तो ताला लगा है कि उस घर के पांच सदस्यों में से तीन किसी शहर में हैं। शहर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी या बगल का कस्बा भी। जिसको जहां नौकरी मिली, कम से कम उसका परिवार वहीं रह रहा है। सरकारी तंत्र की शिक्षा पर विशेषकर राज्यों की ओर से खूब खर्च हो रहा है। अध्यापक भी तैनात हैं। कागजों में ग्रामीण स्कूलों को सहूलियतें भी खूब दी जा रही हैं, लेकिन गांवों के स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी माली हालत छोटे स्कूल का खर्च उठाने लायक नहीं है। अन्यथा सभी अपनी हैसियत के मुताबिक महानगर, शहर या बगल के कस्बे के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्ड पर ग्रामीण जनसंख्या अब भी करीब दो तिहाई से ज्यादा है। लेकिन हकीकत में इसकी संख्या बेहद कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 68.8 आठ फीसद जनसंख्या गांवों में रहती थी। लेकिन भारत सरकार के हालिया अनुमानों के मुताबिक, करीब 63 प्रतिशत जनसंख्या ही गांवों में रह रही है। लेकिन यहां एक बार फिर ध्यान देने की है कि इसका भी बड़ा हिस्सा शहरों में रह रहा है। भले ही शहर में उसकी रिहायश किसी झुग्गी या किसी झुग्गीनुमा शहरीकृत गांव में हो। औद्योगिक इलाकों में रहने वाले लोगों की रिहायशी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हैं, उसकी तुलना में उनका ग्रामीण घर बढ़िया है। फिर भी रोजगार और शिक्षा के लिए कम कमाई के बावजूद ग्रामीण परिवार शहरों में रहने को मजबूर हैं। यह चर्चा लंबी हो सकती है। आज छुट्टियों में हर परिवार अपनी हैसियत के हिसाब से घूमने जा रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर घूमने के लिए पहले की तरह अपने गांवों की ओर नहीं लौट रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के घरेलू पर्यटन में साल 2023-24 की तुलना में 2024-25 में करीब 95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिख रही है। इस साल 250 करोड़ से ज्यादा लोगों ने घरेलू पर्यटन किया। इन पर्यटकों का पूरा विवरण यानी किस इलाके के कितने पर्यटक किस इलाके में घूमने गए। लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज्यादा नए तीर्थस्थलों मसलन काशी के विश्वनाथ कारीडोर, उज्जैन के महाकाल कारीडोर या केदारनाथ आदि की यात्राएं कीं। लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी आता है कि पहाड़ों में लोगों को ठहरने के लिए जगह तक नहीं मिलती, लोग कारों में सड़कों के किनारे ही रहने और अपनी दैनिक क्रिया करने को मजबूर हो जाते हैं। स्पष्ट है कि ये पर्यटक इन जगहों पर जाकर वहां खर्च भी कर रहे हैं। इसका आर्थिक फायदा उन्हीं इलाकों को मिल रहा है।

यहीं पर एक सवाल उठता है कि अगर इन पर्यटकों में से एक हिस्सा अपने गांवों की यात्रा करेगा तो वह जो खर्च करेगा, उस खर्च से उसके गांव-परिवार के आसपास की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसका असर यह होगा कि उन इलाकों में आर्थिक विकास बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से उन इलाकों की सूरत भी सुधरेगी। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के विकास के लिए पूरे परिवेश के योगदान को स्वीकार किया जाता रहा है। इसीलिए व्यक्ति की कमाई और उपलब्धि में उसके परिवेश और परिवार का हिस्सा माना जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शतक वर्ष में पंच परिवर्तन की जो सैद्धांतिकी और कार्ययोजना स्वीकार की है, उसका दूसरा अंग कुटुंब प्रबोधन है। संघ के पंच परिवर्तन में भारतीय संस्कृति की उस अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जिसमें परिवार सिर्फ सामाजिक संस्था नहीं माना जाता, बल्कि संस्कार की प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार्य है। आर्थिक उदारीकरण के बाद जीवन में यांत्रिकता बढ़ी है। इसकी वजह से आपसी संवाद भी घटा है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा तो खैर मिला है, इससे परिवार टूट रहे हैं। ऐसे में कुटुंब यानी परिवार प्रबोधन की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए संघ ने अपने 'परिवार प्रबोधन अभियान' के तहत देशभर में मिलकर भोजन करने, साप्ताहिक पारिवारिक संवाद की परंपरा को बढ़ावा देने, पारिवारिक सांस्कृतिक आयोजन करने जैसी कोशिशें तेज कर दी हैं। घरेलू पर्यटन के तहत अगर लोगों को छुट्टियों में उनके ही गांवों में कुछ दिन गुजारने के लिए अगर प्रेरित किया जाए तो यह कुटुंब प्रबोधन का विस्तार होगा।

वेतन से आगे: विकसित भारत के लिए कुशल कार्यबल की तैयारी

भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ता कार्यबल 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए रोज़गार-आधारित विकास के ज़रिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है।

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

कोयंबटूर में काम करने वाले युवा रवि को, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई में अपनी पहली औपचारिक नौकरी के छह महीने पूरे कर चुके हैं और हाल ही में अपनी मासिक तनख्वाह के अलावा उन्हें बैंक खाते में 7,500 रुपये मिले। लगातार छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम अपने आप जारी कर दी गई। इससे पहले उनका परिवार सिफ़र् अनौपचारिक काम करता था, जिसमें कोई अनुबंध, भविष्य निधि में योगदान या नौकरी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। यह पहला मौका था, जब उनकी नौकरी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया और उन्हें इस तरह का लाभ मिला।

रवि को मिली यह धनराशि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के भाग ए के तहत मिली पहली किस्त है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोज़गार और कौशल पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस प्रावधान के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 15,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है। यह रकम दो किस्तों में दी जाती हैः पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने के बाद। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को ईपीएफओ पोर्टल के ज़रिए वित्तीय साक्षरता का कोर्स पूरा करना होगा और यह राशि बचत के एक साधन में जमा की जाएगी, ताकि कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रवि के लिए, ये छह महीने सिफ़र् योग्यता हासिल करने का समय नहीं थे। ये वो वक्त था, जिसमें उन्होंने अपने काम की जगह को समझा, अपने काम से जुड़ी बुनियादी कौशल और योग्यता सीखी और अपने लिए रोज़गार का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं था।

यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम-वीबीआरवाई के भाग क्च में प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरुआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे-धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। इस शुरुआती लागत को कम करके यह प्रावधान, योजना का दायरा रवि जैसे लोगों को काम पर रखने वाले छोटे व्यवसायों तक बढ़ाता है। उसकी जैसी विनिर्माण इकाईयों के लिए, चार साल की अवधि, जो सामान्य अवधि से दोगुनी है, कंपनियों को ऑटोमेशन में निवेश के साथ-साथ अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ता कार्यबल 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए रोज़गार-आधारित विकास के ज़रिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है। कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोग किस सीमा तक औपचारिक रोज़गार में आते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुरक्षा मिलती है, यह इस बात पर भी असर डालेगा कि परिवारों और समुदायों में विकास का लाभ कैसे मिलता है। पीएम-वीबीआरवाई का मकसद स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक के सफ़र को मज़बूत करना है और दो साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

इस योजना की शुरूआत से, 60 लाख नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से 43.26 लाख (लगभग 71त्न) 18 से 30 साल की उम्र के हैं और 18.04 लाख (लगभग 30त्न) महिलाएं हैं, जो पहली बार औपचारिक रोज़गार से जुड़ी हैं। ये कर्मचारी विशेष सेवाओं, इंजीनियरिंग, व्यापार, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि कई तरह के औपचारिक संस्थानों में इसे अपनाया गया है।

सिफ़र् प्रोत्साहन राशि के अलावा, पीएम-वीबीआरवाई से रवि को एक ईपीएफओ खाता और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला है। इससे वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो भविष्य निधि योगदान, बीमा सुरक्षा और कानूनी रोज़गार लाभ भी देता है। उनके जैसे पहली बार औपचारिक रोज़गार पाने वाले कई लोगों के लिए, यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज और एक व्यवस्थित रोज़गार से जुड़ने का एक बेहतर मौका है। लगातार छह महीने तक नौकरी करने की शर्त का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के तहत बनी नौकरियां असल करियर की नींव बनें। लंबे समय तक औपचारिक रोज़गार से कई क्षेत्रों में नौकरियों में काम आने वाला कौशल विकसित होता हैं, पेशेवर तौर-तरीके सीखने को मिलते हैं और भविष्य में नौकरी पाने की क्षमता भी मज़बूत होती है। इससे मिलने वाले फ़ायदे योजना के तहत मिलने वाली मदद की अवधि के बाद भी बने रहते हैं।

रोज़गार के मौके पैदा करना एक अहम नीतिगत लक्ष्य है। उतना ही ज़रूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि रवि जैसे कर्मचारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाए रख सकें, जहाँ रोज़गार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज और संस्थागत सुरक्षा भी मिलती है। जैसे-जैसे ज़्यादा युवा कर्मचारी औपचारिक नौकरियों में छह महीने, एक साल और उससे ज़्यादा समय बिताते हैं, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है और छोटे संस्थान भी औपचारिक तरीके से लोगों को काम पर रखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिलने का अनुमान है और औपचारिक अर्थव्यवस्था का यह धीरे-धीरे बढ़ता दायरा ही वह बदलाव है, जिसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पीएम-वीबीआरवाई को लाया गया है।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं)

टिप्पणी

बढ़ती आर्थिक चुनौतियां

वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन कारणों से दुनिया नया आकार ले रही हैः महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का वर्चत्व। इसके अनुरूप ढलने के लिए भारत के पास बहुत कम वक्त है।

बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए बदलावों से तालमेल बनाने के लिए भारत के पास एक बहुत छोटी खिड़की मौजूद है। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्थायी संसदीय समिति के सामने कही। बताया गया कि चीन ने अपने नए कानून के तहत वहां स्थित आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। वहां से अपने कारखाने हटाने वाली कंपनियों को वह दंडित कर रहा है। इससे भारत में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीति के सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समय ये तीन परिघटनाएं दुनिया को नया आकार दे रही हैः बड़ी ताकतों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का प्रभुत्व।

मंत्रालय ने कहा कि इन परिवर्तनों पर भारत को अधिक फुर्तीला और रणनीतिक प्रतिक्रिया दिखानी होगी। ऐसा करने के लिए देश के पास 'बहुत छोटा अवसर' है। मंत्रालय ने कहा कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के तहत व्यापार, तकनीक, और वित्त का उपयोग सामान्य लाभ उठाने के बजाय रणनीतिक हितों के मुताबिक किया जा रहा है। इसी क्रम में चीन ने अपने यहां से कारखाना, तकनीक, या विशेषज्ञों को दूसरे देशों में- खासकर भारत ले जाने की राह में कानूनी रुकावट खड़ी कर दी है। भारत में साझा उद्यम या देशी निवेश के तहत लगाए जा रहे कारखानों की इन मामलों में चीन पर निर्भरता रही है। स्पष्टतः ये दोनों परिघटनाएं भारत के लिए चुनौती बनकर आई हैं।

हालांकि यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ती दरार को वित्त मंत्रालय ने भारत के लिए अवसर के रूप में देखा है, मगर इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत खुद को तैयार करने की चुनौती उसके सामने है। मंत्रालय ने माना कि इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कहा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय को बदल रही दुनिया का सही अहसास है। मगर, नई परिस्थितियों के मुताबिक नजरिए एवं नीतियों में जिस तरह के आमूल परिवर्तन की जरूरत है, उसकी समझ का संकेत उसने नहीं दिया है। क्या बिना घरेलू बाजार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए, नए बाहरी हालात का मुकाबला किया जा सकता है- यह बुनियादी सवाल है।

ब्लॉग

बिना वेतन की इंटर्नशिप तोड़ रही भारत के मध्यवर्ग का भरोसा

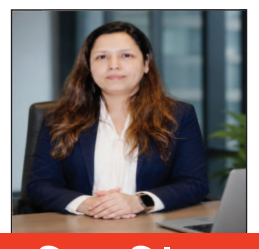

निशा सिंह

दिल्ली में एक युवक, जो उस्मानाबाद से आया है, अपना नाश्ता समेटकर दोपहर के भोजन के लिए रख रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से इंटर्नशिप के लिए मिलने वाले मासिक 5,000 रुपये उसके लिए उस शहर में, जहाँ उसे अवसर पाने के लिए रहना पड़ रहा है, किराया और भोजन दोनों का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसकी यह जद्दोजहद इसलिए नहीं है कि वह अयोग्य है। वह इसलिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसे अवसर की पहली सीढ़ी देने के लिए बनाई गई व्यवस्था की संरचना ही ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़ी है, जिसके पास पहले से आर्थिक सहारा, पारिवारिक समर्थन और जोखिम उठाने की क्षमता मौजूद है। भारत में बिना वेतन वाली इंटर्नशिप की यही मौन क्रूरता है।

हम इसे इस रूप में नहीं देखते। हम इसे "उद्योग का अनुभव", "व्यावहारिक सीख" और "जीवनवृत्त सुदृढ़ करने" जैसे आकर्षक नाम दे देते हैं। इन शब्दों का आवरण हटा दें, तो जो शेष बचता है वह एक सीधा-सा सौदा है; एक युवा का श्रम, उस अवसर के बदले जिसमें प्रवेश पाने के लिए किसी परिवार की आर्थिक सहायता अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। आँकड़े इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। वर्ष 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 35 प्रतिशत इंटर्नशिप ऐसी थीं जिनमें कोई मानदेय नहीं दिया गया, जबकि 25 प्रतिशत इंटर्नशिप में मासिक भुगतान 3,000 रुपये से भी कम था। सर्वेक्षण के आँकड़े यह भी बताते हैं कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के बीच बिना वेतन वाली इंटर्नशिप तेजी से सामान्य होती जा रही है और हाल के वर्षों में इसमें भागीदारी न केवल बढ़ी है, बल्कि इसे पेशेवर सफलता की लगभग अनिवार्य शर्त की तरह स्वीकार भी किया जाने लगा है। यह कोई हाशिये की समस्या नहीं रह गई है; यह अब उच्च शिक्षा और रोज़गार के बीच के संक्रमण काल का एक संस्थागत सामान्य बनती जा रही है। इसका मूल्य कौन चुका रहा है? न कंपनियाँ, न वे संस्थान जो इंटर्नशिप को अनिवार्य बना रहे हैं। यह बोझ सीधे परिवारों पर आ गिरता है, विशेषकर उस मध्यवर्गीय परिवार पर, जिसने अपने बच्चे की डिग्री के लिए दस-दस वर्ष तक बचत की और फिर यह जाना कि अब उस डिग्री को रोज़गार में बदलने से पहले एक अवैतनिक प्रशिक्षुता की अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।

इस क्रूरता का एक ठोस रूप भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई में न्यूनतम प्लेसमेंट वेतन वर्ष 2023 के छह लाख रुपये वार्षिक से घटकर 2024 में चार लाख रुपये रह गया, और उसी वर्ष देशभर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लगभग 21,500 स्नातकों में से करीब 8,000 बेरोज़गार रह गए। जब शीर्ष संस्थानों के विद्यार्थियों के सामने भी रोज़गार का संकट खड़ा है, तब नीचे की पायदानों पर खड़े युवाओं पर किसी भी कीमत पर वेतन सहित या बिना वेतन इंटर्नशिप करने का दबाव और बढ़ जाता है। तीसरे दर्जे के शहर के किसी राज्य महाविद्यालय की छात्रा के लिए 'ना' कहना संभव नहीं होता। इसलिए वह 'ना' नहीं कहती, क्योंकि उसके सामने विकल्प अवसर और शोषण के बीच नहीं, बल्कि अवसर और बहिष्कार के बीच खड़ा होता है।

निम्न-मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बिना वेतन वाली इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर जाना अक्सर संभव ही नहीं होता। परिणामस्वरूप, उन्हें उस व्यावसायिक अनुभव से हाथ धोना पड़ता है, जो आजकल भविष्य की नियुक्तियों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। यहीं से अवसरों की खाई और चौड़ी होने लगती है। विशेषाधिकार प्राप्त छात्र अपना जीवनवृत्त मजबूत करता है; योग्य किन्तु संसाधनविहीन छात्र कर्ज़ का बोझ उठाता है।

इस स्थिति को और भी अस्वीकार्य बनाने वाली बात यह है कि इसे कानूनी अस्पष्टता और नीतिगत उपेक्षा का एक प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। भारत में श्रम संबंधी कानूनों का विस्तृत ढाँचा है- औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं। इसके बावजूद इंटर्नशिप अब भी श्रम कानूनों की मूल सुरक्षा से लगभग बाहर है। नतीजतन, प्रशिक्षु ऐसे कानूनी निर्वात में खड़े हैं, जहाँ वे संस्थानों और संगठनों के लिए वास्तविक मूल्य तो पैदा करते हैं, पर बदले में पारिश्रमिक, कार्य-घंटों की मर्यादा और बुनियादी सुरक्षा जैसे अधिकारों के मामले में लगभग असुरक्षित बने रहते हैं।

सरकार की ओर से वर्ष 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसका लक्ष्य पाँच वर्षों में एक करोड़ इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है, दिशा की दृष्टि से सही अवश्य है, पर वर्तमान स्वरूप में यह उस आर्थिक वास्तविकता का पर्याप्त उत्तर नहीं देती, जिसका सामना इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को रोज़मर्रा के जीवन में करना पड़ता है। पहले चरण में 1.27 लाख इंटर्नशिप के लिए 1.81 लाख लोगों ने आवेदन किया, लेकिन प्रस्ताव केवल 60,000 लोगों को मिले और जो 5,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया, वह किसी भी महानगर में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, जहाँ केवल किराया ही इस राशि से अधिक हो सकता है। नीयत सही है, पर हिसाब गलत है।

समाधान जटिल नहीं है। इसके लिए किसी नई खोज से अधिक राजनीतिक और नीतिगत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। चार सप्ताह से अधिक अवधि वाली हर इंटर्नशिप के लिए शहर के जीवन-यापन व्यय के अनुरूप एक वैधानिक न्यूनतम मानदेय अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो संस्थान या कंपनियाँ इंटर्नशिप के नाम पर कर-लाभ या सामाजिक दायित्व के अंतर्गत श्रेय प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए कि वे पारिश्रमिक संबंधी प्रावधानों का पालन कर रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कार्य-समेकित शिक्षण पर उचित बल दिया है, किंतु यदि उसमें न्यूनतम मानदेय का स्पष्ट प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो उसकी समावेशिता का वादा कागज़ पर ही खोखला रह जाएगा।

भारत का मध्यवर्ग एक भरोसे पर खड़ा हुआ है; ईमानदारी से परिश्रम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और व्यवस्था उस प्रयास का प्रतिफल देगी। बिना वेतन की इंटर्नशिप इसी भरोसे को उसके सबसे नाज़ुक मोड़ पर तोड़ देती है, शिक्षा से रोज़गार की ओर बढ़ने के उस संक्रमण बिंदु पर, जहाँ परिवार का त्याग आर्थिक उन्नति में बदलना चाहिए था। आज हम उन्हीं विद्यार्थियों से कह रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे कम सुरक्षित है, कि वे उस अनुभव की कीमत भी स्वयं चुकाएँ जिसका सबसे अधिक लाभ उन संस्थाओं को मिलेगा जो उनके श्रम का उपयोग कर रही हैं। फिर हम आश्चर्य करते हैं कि छोटे शहरों की प्रतिभाएँ शीर्ष तक क्यों नहीं पहुँच पातीं। इंटर्नशिप को एक सेतु होना चाहिए था। पर बहुत-से युवा भारतीयों के लिए वह अब एक चुंगी नाका बन चुकी है, ऐसा नाका, जिसकी कीमत उसी मुद्रा में चुकानी पड़ती है, जो हर परिवार के पास समान मात्रा में उपलब्ध नहीं होती—आर्थिक सुरक्षा, शहरी ठहराव का खर्च और बिना तत्काल आय के कुछ महीने निकाल सकने की क्षमता। यह योग्यता-आधारित व्यवस्था नहीं है। यह तो अवसर की भाषा में सजाकर परोसी गई ऐसी विशेषाधिकार-प्रधान व्यवस्था है, जिसमें प्रतिभा से अधिक महत्व उस सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हो जाता है, जिससे कोई छात्र आता है।

(लेखिका भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ एक कार्यबल विकास और कौशल नीति के रूप में कार्यरत हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

मंदिर में चढ़ावा चोरी: एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, बड़े पैमाने पर चोरी के संकेत, एफआईआर की सिफारिश

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसआईटी अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमीशनखोरी के खेल उजागर होने की बात कही गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में भी बड़े हेरफेर की आशंका एसआईटी ने जताई है। इनसे संबंधित एक-एक साक्ष्य एसआईटी ने जुटाए हैं। गवाहों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर उनके रिश्तेदारों, करीबियों और कर्मचारियों की भूमिका पर रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं।

एसआईटी में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शासन पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने गोपनीय जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दी। गृह विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़े सवाल उठाए गए हैं। कुछ की भूमिका भी उजागर की गई है। अंदेशा जताया गया है कि वे हेरफेर में शामिल रहे हैं। वहीं, कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है, जिनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी हुआ। फिलहाल मामले में सबसे अधिक जो पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं, उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा व निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल है।

सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान अहम

सूत्रों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के साक्ष्य एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में शामिल किए हैं। वहीं, कुछ अहम फुटेज एसआईटी को मिले भी हैं, जिससे चोरी के आरोपों पर मुहर लगी है। इसमें गणनाकर्मी सीधे तौर पर शामिल रहे। खासकर अनुकल्प, मनीष, अवनीश आदि हैं। इसके अलावा टिन्नू के खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। चोरी में 25-30 लोगों की भूमिका पाई गई है। इन सभी पर एफआईआर की संस्तुति की गई है। इन सभी के खिलाफ कई गवाह भी हैं, जिनके बयान बेहद अहम हैं।

कमीशन का आरोप बनेगा गले की फांस

ट्रस्ट के पदाधिकारियों के रिश्तेदार व करीबियों का भी जांच रिपोर्ट में जिक्र है। खासकर चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा के रिश्तेदार, गोपाल राव के रिश्तेदार सोम आदि का। अब इन सभी पर जल्द केस दर्ज हो सकता है। वहीं, अनिल मिश्रा पर 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोपों का भी जिक्र एसआईटी ने किया है। इंजीनियर ने अपने बयान में भी स्पष्ट रूप से कमीशन का आरोप लगाया है। चंपत राय और गोपाल राव पर भी लगे आरोपों को एसआईटी ने जांच में शामिल किया है। निर्माण के दौरान पत्थरों की खरीदारी में गोपाल की प्रमुख भूमिका थी।

बैंक अधिकारी, कर्मी व पुलिस पर भी सवाल

गणना प्रक्रिया में बैंक की भूमिका अहम रहती थी। लिहाजा, एसआईटी ने बैंक अधिकारियों व उनके कर्मचारियों को भी दोषी पाया है। कुछ की मिलीभगत भी पाई गई है। यही नहीं, संविदाकर्मियों के हवाले गणना व्यवस्था को छोड़ देना और उसमें भी ट्रस्ट की सिफारिशों पर भर्ती करना सबसे बड़ी खामी के रूप में उजागर हुआ है। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर रकम मंदिर परिसर से जाती रही और पुलिसकर्मियों को भी भनक नहीं लगी। इसका जिक्र एसआईटी में किया गया है। जिससे पुलिसकर्मी भी सवालों के घेरे में आए हैं। उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है।

अंदेशा... शायद कुछ ऐसा हो

सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। क्योंकि गणना प्रक्रिया में इनकी भूमिका रहती थी। निगरानी में नाकामी चोरी की बड़ी वजह रही। इसलिए शायद इन सभी को लापरवाही का दोषी बनाया जाए। हालांकि, अनिल व गोपाल पर कानूनी शिकंजा भी कस सकता है।

प्रमुख सिफारिशें... जारी रहेगी जांच

एसआईटी ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की है। नए तरीके से कर्मियों की भर्ती कराने की संस्तुति की है। चूंकि मामले में चोरी व कमीशनखोरी के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए एफआईआर की सिफारिश कर विस्तृत जांच की बात कही है। एसआईटी को और समय मिल गया है। करीब दो सप्ताह बाद जांच कर विस्तृत रिपोर्ट एसआईटी सौंपेगी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट को घर की कंपनी की तरह चला रहे थे ये दो बड़े पदाधिकारी, हर फैसले में मनमानी

राम मंदिर ट्रस्ट को खुद की कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। किसको नौकरी पर रखना है, किसको क्या काम देना है..ये सब चंद लोग तय करते थे। इसमें ट्रस्ट के महासचिव, एक सदस्य व एक निर्माण सहायक की भूमिका रहती थी। प्रबंधन के हर कार्य में इन सभी का हस्ताक्षेप रहता था। पूरी मनमर्जी चलती थी। कोई अन्य इसमें हस्ताक्षेप करे तो वह बर्दाश्त नहीं होता था। यही वजह है कि खेल पर खेल होते गए और चंद लोग मौज करते रहे। आंखों के सामने से चढ़ावा गायब होता रहा और कमीशन का खेल होता रहा। फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया गया था। फिर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 2024 में मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस दौरान व इसके बाद जो भी कार्य मंदिर से जुड़े हुए उनमें सबसे अधिक भूमिका महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के साथ निर्माण सहायक गोपाल राव की रही। ट्रस्ट के इन सभी पदाधिकारियों ने एक के बाद अपने रिश्तेदारों को मंदिर प्रबंधन से जोड़ा। फिर इन सभी अपने करीबियों को जोड़ते गए। एक तरह से ट्रस्ट को खुद की कंपनी बना दी। जिसको चाहा नौकरी देते रहे। यही नहीं मनचाही ड्यूटी भी इन लोगों को सौंपी गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टिन्नू यादव रहा जो ड्राइवर होकर दान की राशि की गणना व चढ़ावे का हिसाब किताब देखता रहा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ट्रस्ट को मजाक बना दिया गया। मामूली कर्मचारी टिन्नू यादव का गणना प्रक्रिया में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। यहां तक कि दान पात्रों की चाबियां उसके पास रहती थी। वहीं जिस कमरे में गिनती होती थी वहां की भी चाबी उसके पास रहती थी। ट्रस्ट में कुल 14 पदाधिकारी (पदेन मिलाकर) हैं। सवाल उठता है कि आखिर अन्य सदस्यों ने इसमें दखल क्यों नहीं दिया। उनका हस्ताक्षेप न करना दो तीन पदाधिकारियों के लिए संजीवनी बन गया। चंपत राय, अनिल मिश्र व गोपाल राव जो करते रहे वह होता गया। क्योंकि कई मामले पहले भी सामने आए, अगर उसी समय सख्ती की जाती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी कह चुके हैं कि गाइडलाइन का सिर्फ दस फीसदी ही पालन हुआ। अगर ऐसा हुआ तो अन्य पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि व्यवस्था में दखल देते। जिससे उसको सुधारा जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि अब चर्चा है कि जिन पर सवाल उठे हैं उनसे पूरी जिम्मेदारी ले ली गई है। डीएम अयोध्या की निगरानी में प्रबंधन काम कर रहा है। गणना की विशेष निगरानी की जा रही है। जिससे किसी तरह की गड़बड़ियां न हों।

शिक्षकों को जागरूक रहने की जरूरत: डॉ. जितेंद्र प्रसाद मिश्र

अयोध्या। समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अयोध्या पर शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह की अध्यक्षता एवं महासचिव डॉक्टर घनश्याम यादव के संचालन में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाधान पर विचार किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मण्डल प्रभारी अयोध्या डॉ. जीतेन्द्र प्रसाद मिश्र मौजूद रहे। शिक्षक सभा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा आज के समय में शिक्षकों को जागरूक रहने की जरूरत है उन्होंने कहा शिक्षक हीं समाज का मार्गदर्शन करते हैं उन्होंने कहा हमें संगठित होकर जनता को जागरूक करना है और सपा की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करना है जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने कहा आज भाजपा के शासन मे सबसे ज्यादा काम शिक्षकों से लिया जा रहा है।

उज्जैन लैंड डील से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक सरकारों पर लगाए गंभीर आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को सुल्तानपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में कथित करोड़ों रुपये के लैंड डील घोटाले का आरोप लगाया, वहीं लखनऊ अग्निकांड को लेकर योगी सरकार की कार्यप्रणाली और दमकल विभाग पर भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने दावा किया कि उज्जैन में जिस धार्मिक क्षेत्र के विकास के नाम पर सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है, उसी इलाके में मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीद की गई है। उनके अनुसार, मंदिर क्षेत्र के आसपास 253 से 335 एकड़ तक जमीन परिवार से जुड़े लोगों ने खरीदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से जानकारी देकर कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि में बदलने की तैयारी की गई और उसके बाद जमीन खरीदी गई। संजय सिंह ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि यदि ऐसी कार्रवाई विपक्ष के किसी नेता से जुड़ी होती तो अब तक जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होतीं। इसके अलावा सांसद ने लखनऊ की एक कोचिंग संस्थान में लगी आग का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब भवन को केवल एक मंजिला निर्माण की अनुमति थी, तो चार मंजिला इमारत कैसे संचालित होती रही। उन्होंने कहा कि वर्षों से टैक्स और अन्य सरकारी शुल्क वसूले जा रहे थे, फिर प्रशासन को अवैध निर्माण की जानकारी क्यों नहीं थी। दमकल विभाग को लेकर भी संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विभाग के एक कर्मचारी के दावों का हवाला देते हुए कहा कि 3 लाख रुपये की बुलेट मोटरसाइकिल को 11 लाख रुपये में खरीदे जाने का आरोप सामने आया है।

लाठी और सरिया से पिटाई, फिर पैरों पर चढ़ा दी बाइक ; अवैध खनन की शिकायत पर युवक संग की बर्बरता

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र के गांव भैरई में खनन की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने युवक पर लाठी, डंडे, सरिया आदि से जानलेवा हमला कर दिया।

मारपीट के बाद युवक के पैरों पर बाइक चढ़ा दी और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गांव के ही चार नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव भैरई निवासी विनोद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने इलाके में हो रहे अवैध बालू खनन की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। इसको लेकर दबंग उससे रंजिश मानने लगे।

पीड़ित सोमवार देर शाम करीब साढ़े 8 बजे गांव में धर्मशाला पर बैठे थे। आरोप है कि तभी अजीत, अरविंद, अजय और आकाश वहां पहुंचे। चारों ने आते ही विनोद को घेर लिया और हमला कर दिया। बेरहमी से पिटाई के बाद आरोपियों ने विनोद के पैरों पर बाइक चढ़ा दी। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सीओ अमरनाथ यादव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चारों नामजदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

लोक कला कार्यशाला का का हुआ शुभारंभ

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। लोक कला संग्रहालय लखनऊ तथा स्वदेश संस्थान, सागर कला भवन अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन लोक कला कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूर्या तिवारी, पार्षद कल्याण सिंह वार्ड, नगर निगम अयोध्या के करकमलों द्वारा हुआ इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष एवं कार्यशाला संयोजक एस. बी. सागर प्रजापति द्वारा अतिथियों के साथ ही प्रतिभा यादव एवं अरुण यादव जी को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र आदि के साथ सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक इमरान खान एवं वीरेंद्र कुमार कुमार तथा कला साधकों में मुख्य रूप से अंशिका मौर्या, अक्षत सिंह, शालिनी साधवानी, सिद्धि राजपाल, विक्रान्त मौर्या सहित अन्य कई कला साधक उपस्थित रहे। एस. बी. सागर प्रजापति ने बताया कि कार्यशाला में लोक कला विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के कलात्मक अभिरुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्यशाला के समापन समारोह में हस्त निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा सभी प्रतिभागियों को लोक कला संग्रहालय लखनऊ, उ प्र द्वारा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। छात्र - छात्राओं में लोक कला की अभिरुचि जाग्रत करने एवं कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा लोक कला को कैरियर के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रतिभाग करने हेतु हेल्पलाइन नम्बर 8874478080 पर सम्पर्क करके सागर कला भवन, नाका चुंगी अयोध्या में आकर आवेदन कर सकते हैं।

न्यूरोप्लास्टिसिटी लाती है दृढ़ता व मनोशक्ति: डा. आलोक मनदर्शन

अयोध्या। स्वस्थ व्यवहार के जागरूक अभ्यास से कुछ ही हफ्तों में दिमाग के सॉफ्टवेयर में इस व्यवहार की प्रोग्रामिंग हो जाती है जिसे न्यूरोसाइंस में न्यूरो प्लास्टिसिटी या ब्रेन- रिवायरिंग कहा जाता है। इस मनोक्रिया का उपयोग संज्ञान व्यवहार उपचार यानि काग्निटिव बिहैवियर थिरैपी-सीबीटी में रुग्ण मनोवृत्तियों की स्वष्थ मनोक्रियाओ से प्रतिस्थापन में की जाती है। यह बातें पैका स्किल्स सभागार में आयोजित मेंटल-हेल्थ व्याक्खान सत्र में डा आलोक मनदर्शन ने कही। उन्होंने कहा मनोरसायन सेरोटोनिन मेन्टल-रेजीलिएंस विकसित कर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, पर इसकी कमी होने पर स्ट्रेस जनित एंग्जाइटी, अवसाद,एंगर,सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ओसीडी, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर,फैमिली कार्नफ्लिक्ट व रिस्क बिहैवियर आदि मनोविकार हो सकते हैं।

गूगल मैप ने बिगाड़ा गांव का नाम, लटक गए सरकारी काम ; आधार कार्ड बन रहा है न जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। डिजिटल युग की इस दौड़ में गूगल मैप ने कितनों की राह आसान की है लेकिन यूपी के फिरोजाबाद जिले के एक गांव के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तहसील सदर और ब्लॉक नारखी के तहत आने वाली ग्राम पंचायत का नाम राजस्व अभिलेखों में आकलाबाद हसनपुर है और गूगल मैप पर इस गांव की लोकेशन अकिलाबाद हसनपुर दिखाई देती है। बस नाम की वर्तनी में जरा सी गलती ने पूरे गांव के सरकारी कामकाज को अटका दिया है। ऑनलाइन पोर्टल (जैसे आधार, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाएं) गूगल मैप का डाटा इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ग्रामीण ऑनलाइन आकलाबाद डालता है, तो सिस्टम लोकेशन मिलान नहीं कर पाता, क्योंकि उसके डाटाबेस में गूगल का अकिलाबाद दर्ज है।

अफसरों ने कागजों पर कर दिया समस्या का निस्तारण

प्रधान नीरज के भाई सोनवीर ने मंगलवार को एसडीएम सदर सतेंद्र सिंह को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि इससे पहले संपूर्ण समाधान दिवस में भी यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे बीडीओ नारखी को भेजा गया लेकिन जमीनी स्तर पर नाम सुधारे बिना, टेक्निकल टीम ने अपनी रिपोर्ट में गूगल के नाम को सही बताकर शिकायत को निस्तारित दिखा दिया।

यह अपनी तरह का पहला मामला है। इसके संबंध में गूगल को पत्र लिखा जाएगा ताकि गांव का सही नाम दर्ज हो सके और लोगों को समय पर उनके दस्तावेज जारी हो सकें। - सतेंद्र सिंह, एसडीएम

ये काम अटक गए

जन्म प्रमाणपत्र : नवजातों के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, जिससे स्कूलों में दाखिले रुक गए हैं।

मृत्यु प्रमाणपत्र : बुजुर्गों व मृतकों के प्रमाण पत्र अटके, जिससे पेंशन, उत्तराधिकार और बीमा जैसे काम ठप हैं।

आधार कार्ड : नए आधार नहीं बन पा रहे और पुराने कार्डों में पता अपडेट होना भी मुश्किल हो गया है।

सरकारी योजनाएं : पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा।

दीर्घ सेतु से आसान होंगी बीकापुर की बड़ी–बड़ी मुश्किलें

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। प्रगतिशील विकास योजनाओं के तहत तमसा नदी पर नेवादा-बिबियापुर मार्ग पर दीर्घ सेतु का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 11.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से बन रहे इस महत्वपूर्ण पुल से बीकापुर विधानसभा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को रफ्तार मिलेगी। विधानसभा क्षेत्र बीकापुर में तमसा नदी पर प्रस्तावित इस दीर्घ सेतु की कुल लंबाई 80.08 मीटर है। इसके साथ ही दोनों तरफ 200-200 मीटर यानी कुल 400 मीटर के पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक निर्माण कार्य भी शामिल हैं। यह पुल न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास, कृषि उत्पादन की बेहतर मार्केटिंग और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच को भी आसान बनाएगा। यह दीर्घ सेतु अयोध्या के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत मील का पत्थर साबित होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ऐसी योजनाएं ही वास्तव में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार कर रही हैं। सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक रोहित अग्रवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2027 तक निर्माण कार्यों की डेडलाइन है। वर्तमान में भौतिक प्रगति 14 प्रतिशत है। सेतु के फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के अनुरूप यह पुल क्षेत्र की पुरानी कनेक्टिविटी समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। तमसा नदी पर पहले से मौजूद पुराने और अपर्याप्त पुल के कारण बरसात के मौसम में आवागमन बाधित हो जाता था। नया आधुनिक दीर्घ सेतु इस समस्या का स्थायी समाधान होगा।

कार्ड बने 'कफन' : हेडलाइट की चकाचौंध बनी काल, एक झटके में बुझे तीन घरों के चिराग, मातम के सिवा अब कुछ नहीं बचा

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव निवासी पिता रामानंद ने बताया कि रामजी चार पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा था। साथ में किसानी में सहयोग कर हाथ बंटाता था। रामजी की मां शोभा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी के सात दिन पूर्व ऐसी दर्दनाक घटना से परिवार सहित चौसड़ और लड़की पक्ष के गांव टोलाकला दोनों गांवों में मातम पसर गया है।

उधर, बिसंडा के पारा बिहारी निवासी मृतक राहुल के मामा सुनील ने बताया कि भांजे राहुल ने पिछले वर्ष ही हाईस्कूल पास किया था। दो भाइयों में बड़ा था। अभी एक वर्ष पहले ही राहुल की मां गिरजा की मौत हो गई थी। घटना से पिता राजकुमार समेत सभी परिजन रो-रोकर बुरा हाल है।

बिसंडा के चौसड़ निवासी मृतक राजू के पिता बृजलाल ने बताया कि इकलौता बेटा था। बुढ़ापे का एक मात्र सहारा था वह भी चला गया। बताते हुए पिता फफक कर रो पड़े और बताया कि बेटे के एक पुत्र व एक पुत्री है। किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना से पत्नी शोभा सहित बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ऐसा था हादसा

अतर्रा थाना क्षेत्र में अपनी शादी का कार्ड देकर घर जा रहे बाइक सवार युवक और मामा की शादी में शामिल होने आए बाइक सवार दो युवकों की बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा बाइकों की हेड लाइट की तेज रोशनी पड़ने की वजह से हुआ। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए।

डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया

तीनों को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव निवासी रामानंद ने बताया कि उसके पुत्र रामजी (22) की शादी सात दिन बाद पहली जुलाई को है।

बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत

बरात बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोलाकला गांव जानी थी। शादी का कार्ड बांटने के लिए खुद रामजी गया था। रात में वापस लौटने के दौरान बिसंडा ओरन मार्ग के चौसड़ गांव के हाऊली बरा के पास सामने से आ रही बाइक उसकी बाइक से टकरा गई।

घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा

हादसे में चौसड़ के बाइक चालक राजू कुशवाहा (40) और पारा बिहारी के राहुल (16) गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां तीनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। चौसड़ गांव निवासी दिलीप कुशवाहा ने बताया कि उसके बड़े भाई सुनील की शादी 24 जून को है।

बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे

शादी में शामिल होने के लिए भांजा राहुल 15 दिन पूर्व आया था। राहुल, गांव के राजू के साथ ओरन मार्ग स्थित दुकान से खरीदारी करने के लिए गए थे। देर रात वह बाजार से लौटते समय हादसा हो गया। बिसंडा थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हुई है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे।

राम मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। अयोध्या धाम स्थित भगवान श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित अनियमितता, गबन और चोरी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और इस दौरान विभिन्न नारों के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन प्राप्त कर राज्यपाल तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि भगवान श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में नकद राशि, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ावे के रूप में प्राप्त होती हैं। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप गंभीर विषय हैं और इनकी स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, मंदिर ट्रस्ट और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि सरकार को इस संवेदनशील विषय पर पारदर्शिता बनाए रखते हुए जनता के सामने तथ्य रखने चाहिए। उनका कहना था कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच आवश्यक है और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शहर अध्यक्ष ने कहा कि भगवान राम देश की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के प्रतीक हैं और यदि चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कोई सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आगे जनजागरण अभियान और आंदोलन चलाने पर विचार करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता हौशला प्रसाद भीम, सलाहुद्दीन हाशमी, रणजीत सिंह सलूजा, निकलेश सरोज, सुब्रत सिंह सनी, अतहर नवाब, मनोज कुमार तिवारी, मो. कमर खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बी12 ही नहीं विटामिन बी में आते हैं कई तत्व

बी 12 की कमी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको कई वीडियो और जानकारियां मिल जाएंगी, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स में कई और तत्व भी होते हैं या कहें कि बी विटामिन के और भी टाइप्स हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

विटामिन हमारे शरीर के फंक्शन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स एक पूरा समूह होता है, जिसमें कई अलग-अलग तत्व होते हैं। बी 1 से लेकर बी 12 तक विटामिन बी में 8 टाइप्स पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग हमेशा बी12 की ही बात करते हैं, लेकिन इस समूह के सभी तत्वों का अपना-अपना रोल होता है। तो चलिए जान लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आने वाले विटामिन के नाम और शरीर में क्या होता है इनका काम।

बी कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर विटामिन शाकाहारी फूड्स में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए फोर्टिफाइड फूड्स या फिर नॉनवेज और सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। फिलहाल हम जान लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स के 8 टाइप्स और इनकी क्या होती है जरूरत।

विटामिन बी 1

बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन है बी 1। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसे थायमिन के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा विटामिन है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसी के साथ ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है।

विटामिन बी 2

बी कॉम्प्लेक्स में दूसरा विटामिन है बी 2। इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये हमारे शरीर में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है और उसे एनर्जी में बदलता है। इसके अलावा ये हमारी आंखों की मोतियाबिंद से सुरक्षा करता है और स्किन को चमकदार बनाए रखने के साथ ही सिर की नसों में होने वाले दर्द और सूजन से बचाव करता है, जिससे आप माइग्रेन जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं। ये डीएनए की मरम्मत के लिए भी जरूरी विटामिन है।

विटामिन बी 3

बी कॉम्प्लेक्स का तीसरा विटामिन है बी 3 यानी नियासिन। ये हमारी पाचन क्रिया और त्वचा की हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ये यूवी किरणों से होने वाले स्किन डैमेज से भी बचाव करता है और प्रीमेच्योर एजिंग को रोकने में हेल्पफुल है। ये भी आपके ब्रेन के लिए जरूरी होता है और जोड़ों के दर्द, सूजन को भी कम करने में सहायक है।

विटामिन बी 5

बी कॉम्प्लेक्स का चौथा विटामिन है बी 5 (पैन्टोथेनिक एसिड)। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस रखने में हेल्प करने के साथ ही आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाता है। मुंहासे, घावों को भरने में भी ये विटामिन हेल्पफुल होता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में मदद करता है, जिससे दिल हेल्दी रहता है।

विटामिन बी 6

बी कॉम्प्लेक्स का पांचवा विटामिन बी 6 (पायरिडोक्सिन) है। ये RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करने के साथ ही प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। मेटाबॉलिज्म को सही रखने से लेकर ये आपके ब्रेन के विकास में अहम भूमिका निभाता है। ये सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे मूड बेहतर होता है।

विटामिन बी 7

बी कॉम्प्लेक्स का छठा विटामिन है बी 7 यानी बायोटिन...इसके बारे में भी ज्यादातर लोगों को पता होता है। ये आपके बालों और त्वचा के साथ ही नाखूनों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होता है। इसकी कमी से बाल झड़ने से लेकर त्वचा पर लाल चकत्ते बनना और नाखून कमजोर होकर टूटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये विटामिन डीएनए और जीन एक्टिविटी को रेग्युलेट करने के लिए जरूरी होता है।

विटामिन बी 9

प्रेग्नेंसी के दौरान कहा जाता है कि फोलेट बेहद जरूरी होता है ये बी कॉम्प्लेक्स में बी 9 का नाम है और ये 8वां टाइप है। इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। ये भ्रूण के विकास में मदद करने के साथ ही डीएनए निर्माण और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये शरीर में होमोसिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के स्तर को कंट्रोल करके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

विटामिन बी 12

बी कॉम्प्लेक्स का आखिरी और 8वां विटामिन बी 12 यानी कोबालामिन जो ज्यादातर नॉनवेज में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसी के साथ डीएनए के लिए भी जरूरी होता है। इसी के साथ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए भी ये बेहद जरूरी विटामिन है। इसकी कमी से एनीमिया की समस्या हो सकती है।

खाना खाते ही सैर पर निकलने की है आदत, एक्सपर्ट से जानें ये कितना सही

सेहतमंद रहने के लिए मॉडर्न तरीकों को अपनाना अब ट्रेंड का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो देखकर लोग सैर के लेटेस्ट तरीके अपना रहे हैं। वॉकिंग के तरीके कई हैं और इससे जुड़े कई सवाल भी लोगों में उठते हैं। इनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या हमें खाना खाते ही तुरंत सैर पर निकलना चाहिए? कहीं इससे हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान तो नहीं होता है। टीवी9 ने जयपुर के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित शर्मा से इस पर खास बातचीत की। उनका कहना है कि खाना खाते ही तुरंत तेज वॉक नहीं करनी चाहिए। ऐसे में पेट में दर्द या डिस्कंफर्ट हो सकता है।

सैर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे अमूमन हर इंसान आसानी से कर सकता है। इसके रूटीन को अपनाने से शरीर को एक साथ कई फायदे मिलते हैं। लेकिन इससे जुड़ी गलतियां भी ज्यादातर लोग दोहराते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि खाते ही सैर करना कितना गलत है?

खाना खाते ही सैर करना

डॉ। रोहित शर्मा कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हैवी एक्सरसाइज या तेज दौड़-भाग करना सही नहीं माना जाता, लेकिन हल्की वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट ने बताया भोजन के तुरंत बाद फास्ट वॉक, जॉगिंग या जिम में हैवी वर्कआउट करना कुछ लोगों में एसिडिटी, पेट दर्द या डिस्कंफर्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि उस समय शरीर का ज्यादा ब्लड फ्लो डाइजेशन प्रोसेस की ओर होता है। इसलिए भोजन के बाद सामान्य गति से, आराम-आराम से वॉक करना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है।

कितनी देर वॉक करना है सही

आमतौर पर 10 से 20 मिनट की हल्की वॉक पर्याप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी कोई गंभीर समस्या, हार्ट डिजीज या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसे अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुल मिलाकर, भोजन के बाद हल्की वॉक एक अच्छी आदत है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाती है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है।

खाने के बाद वॉक करने के फायदे

उनके मुताबिक भोजन के बाद 10-15 मिनट की आरामदायक वॉक डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी लगने जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं। इसके अलावा, खाने के बाद हल्की फिजिकल एक्टिविटी शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी मदद करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज या प्री-डायबिटीज की समस्या है।

ध्यान रखें ये बातें

खाना खाने के बाद भूल से भी जिम में वर्कआउट, रनिंग या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। भारी वजन उठाने जैसी एक्टिविटी से पेट के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके लिए 1।5 से 2 घंटे का गैप रखना बेस्ट रहता है।

सैर करने जा रहे हैं तो टाइट कपड़े या अनकंफर्टेबल फुटवियर से बचें क्योंकि इससे बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। कंफर्टेबल कपड़े और सही फिटिंग वाली जूते पहनकर ही वॉक करनी चाहिए।

खाना खाते ही सैर करने जाते हैं तो इस दौरान थोड़ा-थोड़ा पानी पिएं। ज्यादा पानी पीने से पेट में भारीपन महसूस हो सकता है।

क्या मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी बढ़ जाती है? एक्सपर्ट से जानें सही जवाब

मिसकैरिज के बाद क्या प्रेगनेंट होने के चांस दोगुने हो जाते हैं? ये फर्टिलिटी से जुड़ा एक बड़ा मिथक है जिसे अधिकतर लोग सच तक मान लेते हैं। इस आर्टिकल में एक्सपर्ट के जरिए जानें कि इसमें कितनी सच्चाई है।

प्रेगनेंसी के बाद अगर मिसकैरिज हो जाए तो ये कंडीशन फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रभावित करती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो महिला इमोशनली काफी टूट जाती है। इसके अलावा मन में कई सवाल भी उठते हैं कि क्या फिर से प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी? नेचुरली कंसीव किया जा सकेगा या फिर दवाएं लेनी पड़ेंगी। वैसे मिसकैरिज के बाद क्या फर्टिलिटी बढ़ जाती ऐसे सवाल भी महिलाओं के मन में आते हैं।

इसके बारे में सही जानकारी के लिए टीवी9 ने दिव्या गोस्वामि (कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून) से खास बातचीत की। क्या सच में ऐसा होता है चलिए आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं।

मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी बढ़ती है या नहीं?

दिव्या गोस्वामि (कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून) अक्सर मरीज हमसे पूछते हैं कि क्या मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस विषय को लेकर काफी भ्रम है, इसलिए सही जानकारी देना जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी अपने आप नहीं बढ़ती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भविष्य में गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। यदि मिसकैरिज शुरुआती गर्भावस्था में हुआ है और इसके पीछे कोई गंभीर कारण नहीं है, तो अधिकांश महिलाओं की प्रजनन क्षमता सामान्य बनी रहती है। कई मामलों में महिला का शरीर कुछ ही हफ्तों में ओव्यूलेशन शुरू कर देता है, जिससे दोबारा गर्भधारण संभव हो सकता है। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी बढ़ गई है, जबकि वास्तव में शरीर अपनी सामान्य प्रजनन प्रक्रिया में लौट रहा होता है।

मिसकैरिज के कारण

यह समझना भी जरूरी है कि हर मिसकैरिज का कारण अलग हो सकता है। कभी-कभी क्रोमोसोमल असामान्यताएं, हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड की समस्या, गर्भाशय से जुड़ी स्थितियां या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारण इसके पीछे हो सकते हैं। इसलिए केवल मिसकैरिज के आधार पर फर्टिलिटी के बारे में कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

इन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट कहती हैं कि मिसकैरिज के बाद महिला को शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होने का समय दिया जाए। संतुलित आहार, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार परिवार नियोजन करना महत्वपूर्ण है। यदि बार-बार मिसकैरिज हो रहा है या गर्भधारण में समस्या आ रही है, तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर कारणों की जांच करानी चाहिए।

कुल मिलाकर, मिसकैरिज के बाद फर्टिलिटी बढ़ने का दावा पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन अधिकांश महिलाएं उचित देखभाल और सही स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ सफल और स्वस्थ गर्भावस्था प्राप्त कर सकती हैं।

भारतीयों ने खोला दिल खोलकर खजाना

AC और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड सेल, डबल डिजिट में बढ़े खरीदार!

नई दिल्ली, एजेंसी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती ढाई महीनों में कपड़े, एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल्स में डबल-डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। जो इस बात का भी संकेत है कि लोग अब अपनी पसंद की चीजों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हालांकि, कंपनियों ने चेतावनी दी है कि मानसून की अनियमितता और बढ़ती महंगाई आने वाले महीनों में मांग पर असर डाल सकती है।

कपड़े बेचने वाली कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले सेल्स में 12-14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग में 17-18 फीदसी की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल, AC की बिक्री घटी थी और रेफ्रिजरेटर की बिक्री में सिंगल-डिजिट में बढ़ोतरी हुई थी। GST रेट्स में कटौती और कपड़ों की स्थिर कीमतों से मदद मिली है।

पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर स्थिति

ईरान वॉर से बढ़े जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई की चिंताओं के बीच गर्मी के मौसम वाले प्रोडक्ट्स की मज़बूत मांग ने रिकवरी में मदद की है। डिपार्टमेंट स्टोर चेन 'लाइफस्टाइल इंटरनेशनल' के चीफ एग्जीक्यूटिव देवराजन अय्यर ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा तिमाही में बिक्री बहुत ज़बरदस्त रही है और पिछले साल के मुकाबले इसमें डबल-डिजिट में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी-मार्च में हमने जो खपत में सुधार देखा था, वह और मजबूत हुआ है। हालांकि हाल के महीनों में मांग अच्छी रही है, लेकिन इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कम बारिश के जोखिम के बारे में चेतावनी दी है, जिससे खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं, ग्रामीण इलाकों में परेशानी हो सकती है और ग्राहकों का भरोसा कम हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस मॉनसून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है। जून के आंकड़ों में 46% की कमी देखी गई।

महंगाई में इजाफा

इस बीच, महंगाई में तेज़ी देखी गई है। ईंधन और खाने-पीने की चीज़ों की ऊंची कीमतों के कारण मई में यह बढ़कर 3।93% हो गई, जो अप्रैल में 3।48% थी। पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने से ईंधन की कीमतों को लेकर चिंताएं कम हो सकती हैं, लेकिन अल नीनो का खतरा बना हुआ है। वी-मार्ट रिटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर ललित अग्रवाल ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा तिमाही में सेल्स में डबल-डिजिट की अच्छी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि बारिश के पैटर्न और महंगाई की चाल के आधार पर अब खपत में दिक्कतें आ सकती हैं। पिछले हफ्ते बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि "थोक कीमतों में बढ़ोतरी और अल नीनो के बढ़ते जोखिमों के कारण भारत में रिटेल महंगाई के आउटलुक पर कुछ जोखिम बने हुए हैं।

तेजी से सुधार

कंपनियों और एनालिस्ट्स का कहना है कि फिलहाल मांग अच्छी बनी हुई है। BofA ने कहा कि वैल्यू कॉमर्स मार्केट या थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए ई-कॉमर्स पार्सल शिपमेंट में कोई "साफ सुस्ती" नहीं दिख रही है। ब्रोकरेज ने कहा कि वह ऑनलाइन ट्रैवल और क्विक कॉमर्स को लेकर "ज्यादा उम्मीद" कर रहा है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि बेहतर होते सेंटीमेंट की वजह से AC, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न सेट और वॉशिंग मशीन जैसी सभी कैटेगरी में पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है।

नाम लंबा होने की वजह से अटक रहा टैक्स रिफंड का पैसा? क्या है पूरा मामला

बैंक खाते में लंबा नाम होने के कारण करोड़ों रुपये का टैक्स रिफंड अटक गया है। दरअसल, एनपीसीआई का नया वेरिफिकेशन सिस्टम केवल 50 अक्षरों वाले नाम ही स्वीकार कर रहा है, जबकि बैंकों में 100 अक्षरों तक की छूट है। इस तकनीकी अड़चन की वजह से बड़े विदेशी निवेशकों और पेंशन फंड्स का रिफंड फंस गया है।

टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों और संस्थाओं के लिए एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वित्त वर्ष 2026 से टैक्स रिफंड हासिल करने के लिए बैंक खाते को वैलिडेट करने का एक नया नियम लागू किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के एक नए रियल-टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। लेकिन, शुरुआत में ही इस नए सिस्टम में एक ऐसा तकनीकी पेंच फंस गया है, जिसके कारण करोड़ों रुपये का टैक्स रिफंड अटक गया है। वजह कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं, बल्कि महज बैंक खाते में दर्ज नाम का बहुत लंबा होना है। दरअसल, बैंकों के सिस्टम खाते के नाम में 100 अक्षरों तक की अनुमति देते हैं, जबकि NPCI का नया सिस्टम सिर्फ 50 अक्षरों को ही सपोर्ट कर रहा है।

सिस्टम के बीच फंसा तकनीकी पेंच

यह पूरी अड़चन दो अलग-अलग तकनीकी पैमानों के आपस में न मिलने के कारण खड़ी हुई है। एक तरफ जहां बैंक अपने ग्राहकों को खाते के आधिकारिक नाम में 100 कैरेक्टर तक इस्तेमाल करने की छूट देते हैं, वहीं रिफंड को मंजूरी देने वाला NPCI का वेरिफिकेशन सिस्टम 50 कैरेक्टर पर ही आकर रुक जाता है। जब सिस्टम बैंक खाते के नाम का मिलान करता है, तो नाम की लंबाई अलग-अलग होने के कारण 'मिसमैच' (mis-match) का एरर दिखाई देने लगता है। इस एक साधारण सी तकनीकी खामी के कारण अकाउंट का वैलिडेशन पूरा नहीं हो पा रहा है।

विदेशी निवेशकों पर पड़ा असर

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त कम से कम 10 प्रतिशत FPIs ऐसे हैं, जिनका आधिकारिक नाम 50 अक्षरों से ज्यादा लंबा है। अकाउंट वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण इन संस्थाओं का रिफंड प्रोसेस पूरी तरह से रुक गया है। जानकारी के मुताबिक, हर एक प्रभावित निवेशक का कई करोड़ रुपये का रिफंड इस तकनीकी अड़चन की वजह से फंसा हुआ है। नए नियमों के अनुसार, जब तक बैंक अकाउंट सफलतापूर्वक वैलिडेट नहीं हो जाता, तब तक टैक्स विभाग रिफंड का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता।

क्यों इतने लंबे होते हैं नाम

आमतौर पर एक आम आदमी का नाम काफी छोटा होता है, लेकिन विदेशी फंड्स और पेंशन फंड्स के नाम रखने का एक खास कानूनी और संस्थागत तरीका होता है। इनके आधिकारिक नाम में पहले मुख्य फंड का नाम होता है, उसके बाद फंड मैनेजर का नाम जोड़ा जाता है और अंत में संस्था का स्ट्रक्चर (जैसे Sicav, LLP) लिखा जाता है। इस पूरे लंबे फॉर्मेट की वजह से उनका नाम आसानी से 50 अक्षरों की सीमा को पार कर जाता है। जब ये विदेशी निवेशक NPCI के सिस्टम में अपने नाम के शुरुआती 50 अक्षर दर्ज करते हैं, तो बैंक में मौजूद पूरे नाम से उसका मिलान नहीं हो पाता है।

वित्त मंत्रालय से राहत की उम्मीद

इस गंभीर तकनीकी समस्या को देखते हुए अब कस्टोडियन बैंकों के साथ मिलकर NPCI ने सीधे वित्त मंत्रालय का रुख किया है। मंत्रालय के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बैंक अकाउंट वैलिडेशन के इस नियम से खास छूट देने की मांग की गई है। फिलहाल सभी को सरकार के दखल का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि विदेशी निवेश को सुगम बनाए रखने के लिए सरकार जल्द ही इस मामले में कोई अपवाद (exception) तय करेगी, ताकि फंसा हुआ करोड़ों का रिफंड क्लियर हो सके।

ईरान में रोकी जाए सैन्य कार्रवाई', अपने देश में घिरे ट्रंप, सीनेट में पास हुआ ये प्रस्ताव

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार (23 जून) को ट्रंप प्रशासन के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को समाप्त करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50-48 के करीबी अंतर से पारित हुआ।

जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सीनेट ने ईरान के खिलाफ आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई को सीमित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत भी कर रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी।

सीनेट में पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि 48 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले यह प्रस्ताव अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में भी पारित हो चुका था। यह पहली बार है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव मंजूर किया है।

'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन'

यह प्रस्ताव 'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन' के तहत लाया गया। इसका मकसद राष्ट्रपति की एकतरफा सैन्य कार्रवाई की शक्ति को सीमित करना है। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि ईरान के खिलाफ आसन्न खतरे की स्थिति को छोड़कर ट्रंप प्रशासन बिना कांग्रेस की मंजूरी के कोई हमला नहीं कर सकता। डेमोक्रेट्स के साथ कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी इसका समर्थन किया, जिससे यह 50-48 से पास हो गया।

रिपब्लिकन सांसदों में भी दिखी नाराजगी

सीनेट का मतदान लगभग पार्टी लाइन पर हुआ, लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। वहीं, अधिकांश डेमोक्रेट सांसदों ने इसका समर्थन किया। इधर दो रिपब्लिकन सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इस घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि कि ईरान के साथ जारी तनाव और सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप को अपनी ही पार्टी के कुछ सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मतदान में ट्रंप की पार्टी के चार रिपब्लिकन सांसदों- रैंड पॉल, सुसान कॉलिन्स, लिसा मर्कोवस्की और बिल कैसिडी ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं डेमोक्रेट सांसद जॉन फेटरमैन ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जबकि रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककोनेल और डेव मैककॉर्मिक मतदान में मौजूद नहीं थे। दोनों पहले इस तरह के युद्ध शक्तियों से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का विरोध कर चुके थे।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पास

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भी यह प्रस्ताव मामूली अंतर से पारित हुआ था। वहां 215-208 वोटों से प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसमें चार रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इसका समर्थन किया था।

कितना प्रभावी होगा प्रस्ताव

हालांकि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसके तत्काल प्रभाव को लेकर सवाल बने हुए हैं। वॉर पावर्स एक्ट के तहत यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस नहीं भेजा जाएगा।यह प्रस्ताव 1973 के वार पॉवर्स एक्ट के तहत पारित एक प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती और न ही यह कानून का रूप लेता है। इसी वजह से इसका प्रशासन पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी असर नहीं पड़ेगा।

ट्रंप प्रशासन ने बताया असंवैधानिक

ट्रंप प्रशासन पहले ही इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए कह चुका है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। प्रशासन का कहना है कि यह अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा से समझौता है।

जानकारों का कहना है कि यह कानूनी तौर पर विवाद का विषय बना हुआ है और संभवतः अदालतों में ही इसका समाधान हो।ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो स्कॉट एंडरसन ने कहा कि कार्यपालिका पक्ष संवैधानिक आधार पर इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकता है और इसे लागू कराने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है।

शांति समझौते की कोशिश

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने और संभावित शांति समझौते की दिशा में बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति बन चुकी है और इस दिशा में बीते दिनों स्विटजरलैंड के जेनेवा में अहम मीटिंग भी हुई। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्धविराम लागू है।दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले ने ट्रंप की विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

न्यूक्लियर इंस्पेक्शन से इनकार, बैलिस्टिक पर बात नहीं...तो क्या ईरान की शर्तों से बिगड़ जाएगी बात?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन तो हो गया है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जो अभी भी अनसुलझे हैं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच आनाकानी चल रही है। वहीं, इस बीच ईरान ने एक ऐसी शर्त रख दी है, जिससे डील पर बात बिगड़ सकती है। तेहरान ने न्यूक्लियर इंस्पेक्शन से इनकार कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं था। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान ने IAEA को न्यूक्लियर इंस्पेक्शन नहीं करने दिया तो ईरान के साथ बातचीत कैंसिल कर देंगे। ऐसे में डील सक्सेस होगी या नहीं इस पर आशंका है।

मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने साफ कहा कि उनके देश की मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी। भविष्य में होने वाली किसी भी वार्ता में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईरान की मिसाइल क्षमता देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है और यह हमले से बचाव का मजबूत साधन है। पेजेशकियान के मुताबिक, अगर ईरान के पास आत्मरक्षा की ये मिसाइलें न होतीं, तो इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को भी उसी तरह बर्बाद कर देता जैसा उसने गाजा के साथ किया। इसमें न तो युवाओं पर रहम करता और न ही बुजुर्गों पर कोई दया दिखाता। उन्होंने पश्चिमी देशों की मानवाधिकार नीति की कड़ी आलोचना की और उनके दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए।

समझौते का हिस्सा नहीं था मिसाइल प्रोग्राम- पाक

उधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत या समझौते का कभी हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी, लेकिन उस पूरी वार्ता में बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा न तो कभी उठा, न चर्चा हुई और न ही समझौते में इसका कोई जिक्र था।

बातचीत में ईरान ने दी थी इसकी मंजूरी- ट्रंप

वहीं, पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान के परमाणु निरीक्षण वाले विवाद पर चिंता जताने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीम के जांच करने वाली बात पर ईरान पहले ही राजी हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं वे पूरी तरह गलत हैं और यह बात वे खुद भी जानते हैं। ट्रंप ने साफ किया कि अंदरूनी बातचीत में ईरान ने मंजूरी दी थी और जांच की पूरी 100 फीसदी तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे सही होते, तो मैं अब तक बातचीत रद्द कर चुका होता।

अमेरिका-ईरान के बीच 14 सूत्रीय MoU

बता दें कि लंबे समय से जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने हाल ही में 14 सूत्रीय MoU पर सहमति जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे मंजूरी दी। औपचारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड में होने थे, लेकिन पहले ही लागू कर दिया गया। इसका मकसद अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करना है। समझौते के बाद 21-22 जून को स्विट्जरलैंड में हाई लेवल टॉक हुई। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने 60 दिनों में अंतिम पूर्ण समझौता करने का रोडमैप तय किया।

बांग्लादेश में भगवान राम का अपमान... भारत ने तारिक सरकार को लगाई फटकार, दे डाली ये बड़ी नसीहत

ढाका, एजेंसी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि इस्लामिक कट्टरपंथियों पर नकेल कसा जाएगा। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है बल्कि उसका दबाव और बढ़ ही गया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के गाइबांधा में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मानवाधिकार संगठन JMBF ने इसको लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि सरकार ने यह फैसला इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के दबाव में लिया।

इसके विरोध में वहां के हिंदू समुदाय ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मशाल जलाकर धार्मिक भावनाओं पर हमले की निंदा की है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने कल यानी मंगलवार को बांग्लादेश सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार वहां के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएगी और हिंदू अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में जैसे ही मंदिर में मूर्ति बनाने की बात सामने आई, स्थानीय इस्लामिक संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध के लिए रैलियां निकाली गईं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सरकारी अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपे गए। माहौल बिगड़ने और हिंसा के डर से मंदिर प्रशासन ने 12 जून को मूर्ति का निर्माण काम रोक दिया।

हिंदू समाज की सुरक्षा को खतरा होने के कारण यह निर्माण रोकना पड़ा। यह घटना बांग्लादेश के अपने संविधान और दुनिया के मानवाधिकार नियमों के खिलाफ है।संगठन ने सरकार से इस पूरे मामले की बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बार-बार टारगेट

बता दें कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बार-बार टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों सांप्रदायिक हिंसा और पूजा स्थलों पर हमलों की घटनाएं समय-समय पर होती रही हैं। अशांति और राजनीतिक अस्थिरता के बाद भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता जताई है। बावजूद इसके चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं।

कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में कभी वापसी नहीं होनी चाहिए: जयराम रमेश

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में इन दिनों नेताओं के पाला बदलने की खबरें सुर्खियों में हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से पिछले कई दिनों से दल बदल की खबरें सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को कभी पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सभी नेताओं, खासतौर पर युवा नेताओं को पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वापस लेने के बारे में सोचना भी शर्मनाक होगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनकी निजी राय है।

इन युवा नेताओं ने बदला पाला

दरअसल पिछले 12 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवरा जैसे कई युवा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जब रमेश से भविष्य में कांग्रेस द्वारा उनकी वापसी पर विचार किए जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को कभी दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए।

'वापसी पर सोचना भी शर्मनाक'

कांग्रेस नेता ने कहा 'मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन सभी के लिए जिन्होंने सत्ता और पद के सुख-सुविधाओं का आनंद लेने के बाद, पार्टी के लाभ उठाने के बाद पार्टी छोड़ी है, उन्हें वापस बुलाने पर विचार करना भी हमारे लिए शर्मनाक होगा, लेकिन भारतीय राजनीति तो भारतीय राजनीति है'।

'विचारधारा के खिलाफ पार्टी में गए'

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालें ने यह साबित कर दिया है कि कौन नेता विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा रहा और कौन नहीं। रमेश के मुताबिक आज कांग्रेस में वही लोग हैं जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसा का नाम नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवरा जैसे कई युवा नेताओं की तरफ था।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग, विशेषकर युवा, जिन्होंने पद का आनंद लिया, सत्ता का लाभ उठाया, पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए, उन्होंने पार्टी छोड़कर एक ऐसी पार्टी में जाने का फैसला किया जो वैचारिक रूप से कांग्रेस के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि ऐसे लोगों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि यह मेरी निजी राय है।

राहुल गांधी के थे करीबी

जयराम रमेश का यह बयान उन नेताओं को लेकर आया है, जिन्हें कभी कांग्रेस की अगली पीढ़ी के नेतृत्व के तौर पर देखा जाता था। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा जैसे नाम शामिल हैं। इन नेताओं को गांधी परिवार और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। लेकिन अलग-अलग समय पर ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद इन नेताओं नेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की।वहीं इनमें से कुछ ने अपनी ही पूर्व पार्टी के नेतृत्व पर निशाना भा साधा।

रमेश ने कहा कि खा युवा नेताओं का पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारियां और अवसर मिले थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसी पार्टी का रास्ता चुना जिसकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल अलग है।

हम कॉलेजियम के फैसलों में दखल नहीं देंगे... जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

नई दिल्ली, एजेंसी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की चयन की प्रक्रिया को लेकर सर्वोच्च अदालत ने बड़ा बयान दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चयन की प्रक्रिया (कॉलेजियम के फैसले) सूचना के अधिकार यानी आरटीआई और न्यायिक समीक्षा के बाहर है। कोर्ट ने कहा कि जजों की चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का यह बयान, उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी का सवाल उठाया गया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम का फैसला उसकी अपनी समझ और संतुष्टि पर आधारित होता है। इसमें ना ही हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी उम्मीदवार की सिफारिश को लेकर याचिकाएं सुनकर या निर्देश जारी करके उसमें कोई कमी निकाल सकते हैं। बेंच ने कहा कि हम कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, जिससे नई-नई मुश्किलें खड़ी हों।

जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हम कॉलेजियम के फैसलों में दखल नहीं देंगे। बेंच ने यह भी बताया कि कुछ उम्मीदवारों को चुनने और उनके नामों की सिफारिश करने से पहले सैकड़ों उम्मीदवारों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है।

कॉलेजियम सिस्टम क्या है?

कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार की व्यवस्था है। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, पदोन्नति यानी प्रमोशन और ट्रांसफर किए जाते हैं। इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि इसमें जजों की नियुक्ति खुद जजों के द्वारा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। वहीं, हाई कोर्ट कॉलेजियम में संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसी कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं।

कैस काम करता है कॉलेजियम?

कॉलेजियम नामों की सिफारिश करता है। इसके बाद नाम सरकार के पास भेजे जाते हैं। सरकार नाम जांच करती है और अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो एक बार वापस भी भेज सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से वही नाम भेजे तो सरकार को मंजूर करना पड़ता है। ऐसा ज्यादातर मामलों में होता है। अंत में राष्ट्रपति नामों पर साइन करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है।

'तुमने लाखों दिल जीते हैं, तुम हकदार हो', आर .माधवन को पद्म श्री सम्मान मिलने पर पत्नी सरिता ने दी बधाई

मशहूर अभिनेता आर माधवन को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते दिन मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवॉर्ड्स दिए। वहीं, अभिनेता माधवन को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उनकी पत्नी सरिता बिरजे ने अभिनेता के लिए खास पोस्ट साझा कर बधाई दी है।

इस वर्ष के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का दूसरा संस्करण बीते दिन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मान से नवाजा। साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा में अपने बेजोड़ अभिनय से दिल जीतने वाले अभिनेता माधवन को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान मिलने पर माधवन ने भारत सरकार का आभार जताया।

पत्नी सरिता बिरजे ने शेयर किया पोस्ट

माधवन को जिस घड़ी पद्म श्री से सम्मानित किया गया, वहां उनका परिवार भी मौजूद रहा। बाद में अभिनेता की पत्नी सरिता बिरजे ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा है, 'बहुत बहुत बधाई, माय लव। पद्मश्री सम्मान तुम्हें मुबारक हो, तुम इसके हकदार हो। तुम्हारे जुनून, कठिन परिश्रम और कला ने अनगिनत लोगों का दिल जीता है। मुझे आज और हमेशा तुम पर बहुत गर्व है'।

माधवन ने जताया फैंस का आभार

अभिनेता आर माधवन ने भी एक अलग पोस्ट साझा कर लिखा है, 'मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने पर बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। इस बड़े सम्मान के लिए मैं भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं महाराष्ट्र सरकार का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया और मुझ पर भरोसा किया। यह दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। मेरी फिल्में देखने, मेरे किरदारों को पसंद करने और इतने साल तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। यह सम्मान जितना मेरा है, उतना ही आप सबका भी है। आपके इसी प्यार की वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं'।

'हीरामंडी' फेम श्रुति शर्मा बोलीं, 'कई बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे छोड़ने पड़ते हैं... उनमें बहुत इंटीमेसी होती है'

अभिनेत्री श्रुति शर्मा ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडीः द डायमंड बाजार' में साइमा का किरदार निभाया था। सीरीज में उनका रोल भले छोटा था, लेकिन ऑडियंस ने उनके अभिनय को काफी पसंद किया। हाल ही में अमर उजाला डिजिटल से खास बातचीत में श्रुति शर्मा ने 'हीरामंडी' के बाद जिंदगी में आए बदलाव, इंडस्ट्री से मिलने वाले प्रस्ताव और 'हीरामंडी 2' को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

श्रुति शर्मा ने कहा, 'हीरामंडी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर्स भी आए। मैंने उसके बाद सीरीज 'मिट्टी' भी साइन की। अब 'ऑफिस ऑफिस - चली मुसद्दीलाल की बेटी' कर रही हूं। दरअसल, मैं हमेशा से बहुत क्लीन वर्क करने में विश्वास करती हूं। अगर मैं कोई काम कर रही हूं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास उसमें सच में कुछ करने के लिए हो। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हूं, जहां मुझे खुद को भी चुनौती देने का मौका मिले।'

श्रुति शर्मा ने बताया कि कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बावजूद वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पातीं। उन्होंने कहा 'आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं लेकिन कई बार उनमें बहुत सारी इंटीमेसी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जिनके साथ मैं सहज नहीं हूं, तो मुझे बहुत बार मना करना पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि मैं किस तरह का काम कर रही हूं।'

कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा

'हीरामंडी' को लेकर मिले प्यार पर श्रुति शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उन्होंने कहा 'सच कहूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आज भी अलग-अलग देशों से मेरे पास संदेश आते हैं। लोग पूछते हैं कि आप दोबारा कब दिखेंगी, हीरामंडी 2 कब आ रही है, हम आपको फिर कब देख पाएंगे।'

हर पल भगवान को धन्यवाद करती हूं

श्रुति ने आगे कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतनी बड़ी कास्ट थी। उसमें मेरे किरदार की आधी ही कहानी सामने आई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे इतना प्यार दिया। मैंने सच में यह सोचा नहीं था। मैं इस चीज के लिए बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है हर पल मैं भगवान को धन्यवाद कहती हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा प्रोजेक्ट दिया।'

'हीरामंडी 2' को लेकर भी श्रुति शर्मा ने अपनी इच्छा जाहिर की। अभिनेत्री ने कहा, 'जहां तक मुझे आखिरी जानकारी मिली है, अभी तो कहानी पर ही काम चल रहा है। मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रही हूं कि कुछ नया सामने आए। सच कहूं, अगर इसकी कहानी आगे बढ़ती है और मुझे मौका मिलता है, तो मैं दोबारा इसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी।'

एक्शन से हटकर अलग अवतार में दिखेंगे टॉम क्रूज, जारी हुआ नई फिल्म 'डिगर' का पहला लुक

हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार टॉम क्रूज जल्द ही 'डिगर' में नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने इस फिल्म की पहली झलक साझा की है। टॉम क्रूज इसे लेकर उत्साहित हैं।

हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। मगर इस बार वह अपकमिंग फिल्म 'डिगर' में एक बिल्कुल अलग अवतार में दर्शकों को हैरान करने के लिए तैयार हैं। इसमें उनके टैलेंट का एक नया और अनोखा पहलू देखने को मिलेगा।

मंगलवार को, ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु की नई ब्लैक कॉमेडी फिल्म 'डिगर' से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सामने आईं। वॉर्नर ब्रदर्स ने टॉम क्रूज के शानदार करियर का जश्न मनाते हुए यह वीडियो जारी किया है, जिसमें फैंस को 'डिगर' की पहली झलक देखने को मिली है।

भले ही यह फुटेज छोटा है, लेकिन इसमें क्रूज को 'डिगर रॉकवेल' के रूप में दिखाया गया है। यह ऐसा किरदार है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। उनके हालिया काम में अक्सर दिखने वाले एक्शन-हीरो वाले अंदाज से बिल्कुल अलग, यह रोल क्रूज को एक डार्क कॉमेडी और अलग दुनिया में ले जाता हुआ लगता है।

फिल्म को लेकर उत्साहित हैं टॉम

इस फुटेज को शेयर करते हुए टॉम क्रूज ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पिछले 46 वर्षों से आप सभी के लिए कहानियां और फिल्में बनाने के लिए अनगिनत टैलेंटेड कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। मैं आपसे सिनेमाघरों में मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं! डिगर इस अक्तूबर सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज होगी।' बताया जाता है कि फिल्म का ट्रेलर 13 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।

नौ साल पहले आया फिल्म का आइडिया

इससे पहले सिनेमाकॉन में बात करते हुए, 'मिशनः इम्पॉसिबल' के एक्टर, इनारितु के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा, 'यह वैसी ही फिल्म है जैसी मैं बनाना चाहता था। यह फिल्म जबरदस्त और मजेदार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे जल्द से जल्द देखें।' डायरेक्टर इनारितु ने बताया कि उन्हें 'डिगर' का आइडिया नौ साल पहले आया था और वह पिछले सात वर्षों से क्रूज के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में क्रूज के अलावा सैंड्रा हुलर, जेसी प्लेमन्स, रिज अहमद, माइकल स्टुलबर्ग, सोफी वाइल्ड और एम्मा डी'आर्सी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

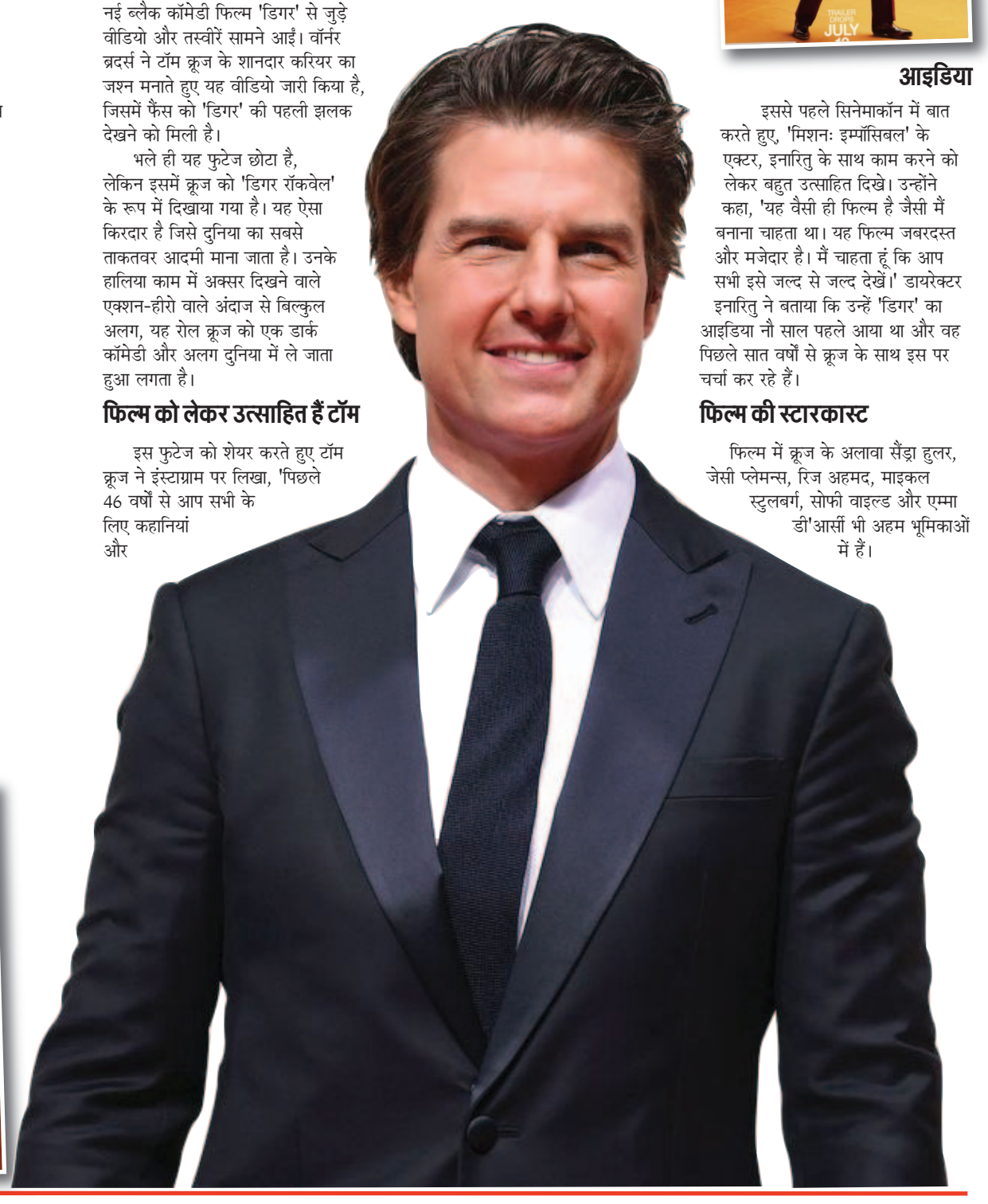

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालयः S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्कः 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com